



राष्ट्रीय

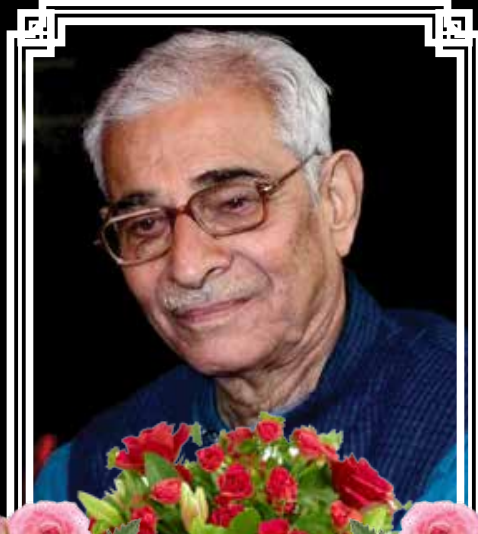
छात्रशक्ति

वर्ष 45 ■ अंक 01 ■ अप्रैल 2023 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40

राष्ट्रीय
एकात्मता
यात्रा-2023



श्रद्धांजलि



स्व. ओम प्रकाश कोहली

(9 अगस्त 1935 - 20 फ़रवरी 2023)

गुजरात के पूर्व राज्यपाल व अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली का निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति: अभाविप

गुजरात के पूर्व राज्यपाल व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर अभाविप कार्यकर्ताओं में शोक की लहर व्याप्त है। अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व गुजरात के पूर्व राज्यपाल प्रो. ओम प्रकाश कोहली जी के निधन पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका निधन संपूर्ण समाज के लिए क्षति है। उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा क्षेत्र तथा समाज जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के निमित्त महत्वपूर्ण प्रयास किए।

ओम प्रकाश कोहली ने छात्र नेता, प्राध्यापक, शिक्षक नेता, राज्यसभा सांसद तथा गुजरात के राज्यपाल आदि जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन करते हुए, देश के युवाओं का मार्गदर्शन किया। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ओपी कोहली लाखों अभाविप कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत रहे।



राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 45, अंक 01
अप्रैल 2023

संपादक

आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनोश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :

राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

✉ rashtriyachhatrashakti@gmail.com

📘 www.facebook.com/Rchhatrashakti

🐦 www.twitter.com/Rchhatrashakti

📷 www.instagram.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।



05

प्रेम और अपनत्व का भाव लेकर लौटे पूर्वोत्तर के छात्र

अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023 का प्रेम, अपनत्व और बंधुत्व की अमिट यादों के साथ...

संपादकीय	04
विकासार्थ विद्यार्थी का कार्य संपूर्ण देश के लिए : प्रफुल्ल आकांत	10
देश की संप्रभुता व एकता सर्वोच्च, खालिस्तान समर्थकों से कड़ाई से निपटे सरकार: अभाविप	11
सहजता व सौम्यता की प्रतिमूर्ति अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. ओम प्रकाश कोहली	12
SHODH DELHI ORGANIZED A LECTURE ON CHANGING CONTOURS OF MULTILATERALISM IN JNU	13
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) : THE WAY FORWARD	14
प्राध्यापक व नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्त पदों को अविलंब भरे बिहार सरकार : अभाविप	17
राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023 की झलकियां	18
दिल्ली का विश्वस्तरीय (अ) शिक्षा मॉडल...!	22
वैज्ञानिक व तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ पाठ्यक्रमों में सुधार आवश्यक: अभाविप	25
बिहार में नियमों से समझौता कर नियुक्त कुलसचिवों को पदमुक्त किए जाने का निर्णय स्वागतयोग्य: अभाविप	26
अभाविप द्वारा पटना में बिहार मंथन कार्यक्रम का आयोजन	27
उत्तर प्रदेश में बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने के निर्णय का अभाविप ने किया स्वागत	28
देश के हर जिले में खुले मेडिकल महाविद्यालय: अभाविप	29
देश में पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक, रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं : अभाविप	30
भारतीय भाषाओं में फार्मसी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और आर्किटेक्चर की पुस्तकें तैयार करने की पहल स्वागतयोग्य : अभाविप	31
उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित वर्गों के छात्रों की ड्रॉप-आउट संबंधी समस्या की हो पारदर्शी जांच: अभाविप	32
95 साल की एथलीट दादी ने पौलैंड में रचा इतिहास, तीन गोल्ड जीत कर बढ़ाया भारत का मान	33
वैदिक ज्ञान परंपरा को सर्वसुलभ बनाने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुभारंभ	34
सरहल पर्व पर रांची में अभाविप ने लगाए सेवा शिविर	35
राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव' मुंबई में संपन्न	36
भारतीय छात्र को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रताड़ित करने तथा भेदभाव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण: अभाविप	37
उड़ीसा में वनवासी विद्यार्थियों के लिए अभाविप ने आयोजित किया एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।



संपादकीय



य

ह जानना सुखद है कि अब उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी भारतीय संदर्भ और उदाहरणों से भारत को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी योजना बनायी है। निस्संदेह यह बहुप्रतीक्षित और स्वागतयोग्य निर्णय है।

भारत एक जीवंत सभ्यता है और हजारों वर्षों के इतिहास में इसने अपने सामने उपस्थित हुई हर समस्या का अपने तरीके से समाधान खोजा है। शताब्दियों के इन अनुभवों ने भारतीय समाज को विषम परिस्थितियों में से विजयी होकर निकलने का सामर्थ्य दिया है। स्वाधीनता के बाद यदि देश इतिहास की तुलना में क्षुद्र स्तर की समस्याओं से उबरने में व्यथित होता रहा तो उसका कारण था कि उसने अपनी समस्याओं का समाधान अपनी ज्ञान परम्परा में खोजने के बजाय विदेशी संदर्भ और विदेशी उदाहरणों की नकल से करने की असफल कोशिश की।

भारतीय ज्ञान परम्परा में न केवल अर्थशास्त्र, कला, प्रौद्योगिकी, रसायन, खगोल विज्ञान तथा कूटनीति आदि का तर्कसिद्ध सैद्धांतिक प्रतिपादन हुआ है अपितु उसका अनुप्रयुक्त पक्ष भी पूर्णतया व्यावहारिक और उपयोगी है। जिन उपादानों के बल पर हमारी विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठा हुई तथा जिस व्यवसायगत उत्कृष्टता के चलते भारत सोने की चिड़िया कहलाया, समय की कसौटी पर खरे साबित होने वाले उन मूल्यों की उपेक्षा कर हम कहीं नहीं पहुंच सके।

पश्चिम की जिन वैज्ञानिक उपलब्धियों के सामने अनेक विद्वान अपने आप को छोटा मानते हैं और आत्मग्लानि से भर जाते हैं, उनमें से कुछ को लेकर पुष्ट प्रमाण हैं कि उनका उल्लेख भारतीय ग्रंथों में है और उन ग्रंथों के अनुवाद के बाद ही यह खोजें हो सकीं। यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि हमारे पास ऐसा अब्दुत ज्ञान था तो वे आविष्कार हमने ही क्यों नहीं कर लिये। उत्तर स्पष्ट है, कोई भी राष्ट्र सबसे पहले अपने-आपको पराधीनता से मुक्त करने के प्रयास करता है। हमने भी वही किया और स्वाधीनता प्राप्त की। दुर्भाग्य से स्वाधीनता पाने के पश्चात अपनी जड़ों की ओर लौटने के जो गंभीर प्रयास किये जाने आवश्यक थे, कतिपय कारणों से वे नहीं हो सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस निर्णय के बाद निश्चित है कि शिक्षा जगत का ध्यान उस धरोहर की ओर जायेगा जिसे हम भुला बैठे हैं। आगे चल कर इन विषयों पर अनुसंधान भी होंगे। स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद भी यदि हम अपनी जड़ों की ओर लौट सकें तो हमें अपना स्वर्णिम इतिहास दोहराने से कोई नहीं रोक सकेगा।

यह परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की शुभकामना के साथ,

आपका
संपादक



राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023 संपन्न प्रेम और अपनत्व का भाव लेकर लौटे पूर्वोत्तर के छात्र

। अजीत कुमार सिंह ।

अं तर-राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023 का प्रेम, अपनत्व और बंधुत्व की अमिट यादों के साथ गुवाहाटी में समापन हो गया। एकात्मता यात्रा का आयोजन गत एक फरवरी 2023 से बीस फरवरी 2023 तक किया गया था। यात्रा में पूर्वोत्तर के सात प्रांतों के 86 जिलों से 460 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया जो पूर्वोत्तर के 81 अलग-अलग वनवासी वर्ग से संबंध रखते हैं। यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम एसआईपीआरडी-गुवाहाटी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वद्यालय के कुलगुरु डॉ. गंगा प्रसाद परसाई एवं असम सरकार के शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगु ने किया। सील प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने

कहा कि पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले वनवासी समाज के यह विद्यार्थी देशभर में पूर्वोत्तर भारत के ब्रांड एंबेसडर बनने वाले हैं।

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा में हिस्सा लेने वाले 460 विद्यार्थियों को 16 अलग-अलग समूहों में बांटा गया। सभी समूहों के नाम पूर्वोत्तर के महापुरुषों व गुमनाम क्रांतिकारियों के नाम पर रखे गए थे। प्रत्येक समूह ने अलग-अलग राज्यों के चार अलग-अलग स्थानों पर 20 दिन की यात्रा की। यह यात्रा 22 राज्यों के 64 स्थानों पर गई। प्रतिनिधियों में ज्यादातर विद्यार्थी ऐसे थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी रेलयात्रा नहीं की थी और अपने प्रांत को छोड़कर कभी बाहर नहीं निकले थे। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र एकात्मता यात्रा में सील प्रकल्प के माध्यम से निकले। जब ये प्रतिनिधि अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते थे तो स्टेशन पर जोरदार स्वागत देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। प्रत्येक स्थान पर सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता



लगाव ऐसा कि एक साल का बच्चा भी फूट-फूट कर रोने लगा

अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन यात्रा में छात्र केवल देश की भौगोलिक सीमा, शैक्षिक और आर्थिक परिसरों को ही नहीं देखते हैं, बल्कि भारत की आत्मा से उसका साक्षात्कार होता है। वह सभी भारत की सांस्कृतिक एकता और भाषाई विविधता से भी परिचित होते हैं। इस यात्रा की विशेषता यह है कि यात्री किसी होटल, सराय या किराए के कमरों में नहीं रुकते बल्कि परिवार में रहते हैं। वह भी ऐसे परिवार में, जिससे पहले कोई परिचय नहीं रहता भारत की एकात्मता देखिये, दो दिन पहले तक पूर्वोत्तर के छात्र जिस परिवार को जानते तक नहीं थे, उसी परिवार से विदा लेने समय छात्रों की आंखें नम हो जाती थी।

ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिला। हल्द्वानी में दो छात्राएं एक परिवार में दो दिन के लिए रुकीं। दो दिन में उनका परिवार के प्रति असीम प्रेम स्थापित हो गया। दो दिन में ही वे इतने घुल मिल गए कि लग रहा था मानों वर्षों से जान-पहचान रही हो। दो दिन साथ गुजारने के बाद माहौल उस समय भावुक हो उठा, जब विदाई के समय उस परिवार का एक वर्षीय बच्चा सील यात्रा पर आए छात्राओं की गोद से उतरने को तैयार नहीं था और ट्रेन चलते वक्त उनकी गोद में जाने के लिए फूट-फूट कर रोने लगा।



ढोल-नगाड़े, बाजे-गाजे के साथ पूर्वोत्तर के मित्रों का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। सभी प्रतिनिधियों की परिवारों में रुकने की व्यवस्था की गयी थी, जिससे उन्हें भारत की अनूठी परिवार व्यवस्था को समझने का मौका मिल सके। इस यात्रा में पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों ने लगभग 960 परिवारों में निवास किया।

सील प्रतिनिधियों ने अलग-अलग राज्यों के ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थानों, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों का भ्रमण किया। बिहार पहुंचे समूह के प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण करके वहां के प्राचीन इतिहास को जाना। सभी 64 स्थानों पर सील प्रतिनिधियों के स्वागत एवं सम्मान हेतु नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों से लेकर आम छात्रों ने भाग लिया।

बिहार की राजधानी पटना में पटना साइंस कॉलेज, आर.एम.आर.आई संस्थान एवं आई.एम.ए. भवन, पटना में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉ. शान्ति राय, पद्मश्री डॉ. विमल जैन, एन.आई.टी पटना के निदेशक प्रो. पी.के. जैन, अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गोविंद नायक आदि शामिल रहे। इस दौरान पटना में सील प्रतिनिधियों ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल से भेंट की एवं पूर्वोत्तर की परंपरा के बारे में उन्हें अवगत कराया। वहीं झारखंड स्थित धनबाद में कोल फील्ड का अवलोकन छात्रों के लिए अनोखा अनुभव था।

प्रतिनिधियों ने न केवल बड़े शैक्षिक संस्थान और महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट से लेकर अस्सी घाट तक का भ्रमण किया। सील प्रतिनिधियों ने लखनऊ विधानसभा का भी भ्रमण किया, वहीं दो समूहों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्रमशः काशी व लखनऊ में भेंट की। उन्होंने इस यात्रा को राष्ट्रीय एकात्मता के लिए आवश्यक बताया और पूर्वोत्तर से शेष भारत के ऐतिहासिक संबंधों के इतिहास के बारे

में प्रकाश डाला। छात्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ-साथ केंद्रीय तिब्बत विश्वविद्यालय भी गए, जहां विश्व विद्यालय के कुलगुरु डॉ. गेशे नवांग समतेन ने प्रतिनिधियों को आशीर्वाद दिया। यात्रा के अंतर्गत कानपुर पधारे पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के ग्रुप मोजी रीबा के लिए 'नागरिक अभिनंदन समारोह' का आयोजन किया गया, जिसमें अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही एवं आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. अभय करंदीकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसी प्रकार मथुरा पहुंचे समूह लचित बरफूकन के प्रतिनिधियों ने भगवान कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए एवं परमशक्ति पीठ, वात्सल्य ग्राम वृंदावन में 'नर सेवा-नारायण सेवा' के भाव को चरितार्थ करने वाली पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं एक अन्य समूह ने अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर का दर्शन किया। इसी प्रकार एक समूह गोरखपुर में गीता प्रेस भी गया।

प्रतिनिधियों का दल देवभूमि उत्तराखंड भी गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधियों से भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने सील यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा देश के युवाओं में विभिन्न राज्यों की परंपराओं की जानकारी के साथ-साथ एकता व समरसता की भावना को और अधिक मजबूत करेगा। गुजरात के कर्णावती पहुंचे सील यात्रियों ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन किया। सरदार पटेल ने किस प्रकार से राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य किया था, यह जानकारी भी समूह ने प्राप्त की। 'राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा' के अंतर्गत गुलाबी नगरी जयपुर पधारे हुए कनकलता बरुआ समूह के प्रतिनिधियों ने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की।

यात्रा के अंतर्गत दिल्ली पधारे हुए मतमुर जामोह समूह के प्रतिनिधियों ने भारत के पूर्व क्रिकेटर एवं वर्तमान में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद गौतम गंभीर से भेंट की और खेल, सेवा, राजनीति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। "राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा" के मतमुर जामोह समूह के प्रतिनिधियों ने माननीया राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू से दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय

किसी ने पहली बार ट्रेन से यात्रा की तो कईयों ने पहली बार देखा समुद्र

5 जी के जमाने में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन से यात्रा नहीं की है। यह पढ़कर भले ही आपको आश्चर्य लग रहा हो लेकिन यह सच है। अभाविप प्रकल्प सील के तहत राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा पर आए कई छात्र ऐसे थे, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ट्रेन से यात्रा की है। उन सभी का कहना था कि सील यात्रा के पहले वे कभी ट्रेन पर नहीं चढ़े थे वहीं महासागर को देखने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इससे पहले दीवारों पर लगे कैलेंडर एवं टेलीविजन पर महासागर को कभी-कभार देखा था। सील के प्रति आभारी हूँ जिसके माध्यम से आज प्रत्यक्ष रूप से महासागर की लहरों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।



सह-संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण एवं अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन (सील) के अध्यक्ष अतुल कुलकर्णी की उपस्थिति में भेंट की एवं राष्ट्रपति भवन के विस्तृत इतिहास को जाना। अंतर-राज्य छात्र जीवन दर्शन की 'राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा-2023' के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के समूह क्रमांक 7 पा-तोगून नेंगमिन्जा संगमा का 'नागरिक अभिनंदन समारोह' जेएनयू, दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान सील यात्रा के इतिहास व इसके उद्देश्य से सभी को परिचित करवाया।

यात्रा के मतमुर जामोह समूह के प्रतिनिधियों का



‘नागरिक अभिनंदन समारोह’ केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं अंतर राज्य-छात्र जीवन दर्शन के अध्यक्ष अतुल कुलकर्णी की उपस्थिति में

दिल्ली विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। इस दौरान सील अध्यक्ष अतुल कुलकर्णी ने सील के जुड़े कई अनछुए पहलुओं से सभी को परिचित करवाया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने इस यात्रा की सराहना की।

सील के कनकलता बरुआ समूह के प्रतिनिधियों ने पंजाब में अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में उत्साहित होकर भाग लिया और जालियांवाला बाग जाकर अंग्रेजों के अत्याचारों की पराकाष्ठा के प्रतीक जलियांवाला नरसंहार के अमर बलिदानियों को नमन किया। जालंधर पधारे वाना पा चानचीन कीमचान (Vana Pa ChanchinKimchan) समूह के प्रतिनिधियों ने साइंस सिटी तथा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों का भ्रमण किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पधारे हुए कनकलता बरुआ समूह के प्रतिनिधियों ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश

अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन

“अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश” के भाव के व्यावहारिक प्रकटीकरण का माध्यम बनी यह यात्रा 1962 के चीन एवं 1965 के साथ हुए पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय एकात्मता को स्थापित करने के उद्देश्य से 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन (student's experience in inter-state living) जिसे सील (SEIL) भी कहते हैं, प्रकल्प की शुरुआत की। ‘सील’ राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कार्य करने की कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरती, संस्कृति से पूरे देश को परिचय कराने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। 1966 से शुरू हुई यह यात्रा बिना किसी ठहराव (कोरोना काल को छोड़कर) के प्रतिवर्ष चल रही है।

सील यात्रा से जुड़े अनेक विद्यार्थी आज न केवल समाज जीवन में पूर्वोत्तर भारत के प्रतिभा का दुनिया से लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि वे भारत माता का मस्तक भी गर्व से ऊंचा करने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर के छात्रों की अखिल भारतीय स्तरीय एकात्मता यात्रा का आयोजन अलग-अलग स्थानों पर होती है, जहां प्रतिभागी विभिन्न परिवारों में ठहरते हैं, जिससे उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ पारिवारिक परिवेश में रहने का अवसर मिलता है। प्रतिभागी जहां भी जाते हैं, वहां की रीति-नीति, सांस्कृतिक-भौगोलिक-सामाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यात्रा के दौरान न केवल वे एकात्मता के बंधन में बंध जाते हैं, बल्कि उस परिवार के साथ उनका नियमित आत्मीय संपर्क भी आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार शेष भारत से भी प्रतिभागी पूर्वोत्तर जाकर वहां की समस्याओं, संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों, परिस्थितियों, संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। पूर्वोत्तर के वनवासी परिवारों में रुक कर उन्हें समझने की कोशिश तो करते ही हैं, बाद में वहां से लौटने के बाद पूर्वोत्तर भारत के बारे में लोगों को बताते हैं।



के संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया गया। साथ ही जम्मू की डोगरी नृत्य भी देखने को मिला। सील के HaipuJa donang Malangmei समूह ने केरल में मार्शल आर्ट्स के सबसे पुराने तरीके कलारीपयट्टु का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखा और समुद्र तट पर भ्रमण का आनंद लिया। चेन्नई पहुंचे समूह ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि से मुलाकात की एवं पूर्वोत्तर के बारे में विस्तृत चर्चा की। माननीय राज्यपाल नागालैंड के भी पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं और इस अवसर पर उन्होंने नागालैंड में अपने बिताए गए समय के अनुभव को भी साझा किया। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के ग्रुप क्रमांक 10 ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौदराजन से राजभवन हैदराबाद में संवाद किया व यात्रा के अनुभव सांझा किए। गोवा में सील के बीर टिकेंद्रजीत सिंह समूह के प्रतिनिधियों के सम्मान में 'नागरिक अभिनंदन समारोह' का आयोजन किया गया, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत एवं अभाविप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रो. अल्लम प्रभु विशेष रूप से उपस्थित रहे। सील प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट की एवं सील यात्रा के बारे में जानकारी साझा की। छात्रों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों से वार्तालाप किया और चारमीनार का भी दर्शन किया। बैंगलोर में गए समूह ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से

भेंट की एवं विधानसभा का परिदर्शन किया। यू तिरोट सिंह समूह के प्रतिनिधियों ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

आर्थिक राजधानी मुंबई में पहुंचे गोपीनाथ बोरदोलौई समूह के प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल से भेंट की। प्रतिनिधियों के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह चर्चगेट स्थित मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ। यह समारोह अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं इस समूह ने प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर से मुलाकात की एवं उनकी आने वाली फिल्म शिवशक्ति बालबोआ का प्रीमियर भी देखा। अनुपम खेर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के सात राज्यों के छात्रों से एक साथ मिलने का सौभाग्य विद्यार्थी परिषद के कारण मिला। 'राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा' के अंतर्गत नागपुर पधारे उ क्रियांग नांगबाह समूह के प्रतिनिधियों ने नागपुर के प्रसिद्ध फुटाला तालाब पर बने देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटैन का आनंद उठाया। इस अवसर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित रहे। नागपुर में सील प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक मोहनराव भागवत जी से भेंट की। ■



विकासार्थ विद्यार्थी का कार्य संपूर्ण देश के लिए : प्रफुल्ल आकांत

वि

कासाथ विद्यार्थी द्वारा 'सृष्टि मंथन' नाम से दो दिवसीय (1-2 अप्रैल) राष्ट्रीय कार्यशाला सह पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन लखनऊ स्थित डॉ. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यशाला के उदघाटन समारोह में अपने संबोधन में अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) का काम संपूर्ण देश के लिए है। एसएफडी वन लाइफ वन मिशन है। ये मिशन पैशन से परिवर्तित होता है। नैसर्गिक विकास एवं विनाश रहित विकास ही सही विकास है। आज दुनिया गोल-गोल घूमकर उन्हीं बातों पर आ रही है, जिनका आधार भारत रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेरा नहीं समाज का मिशन बने इसके लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता है।

पर्यावरणविद एवं विकासार्थ विद्यार्थी के पूर्व संयोजक सचिन दवे ने नर्मदा की सफल अध्ययन यात्रा का अनुभव और जन सहभागिता के माध्यम से समाधान के अभियान कैसे चलाए जा सकते हैं ? विषय पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अभाविप राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। आज यही समाधान का मार्ग है। कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रांत के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रांत के अभियान और काम की जानकारी भी बैठकों और सत्रों में रखी। रात्रि सत्र में ऑस्कर प्राप्त डॉक्यूमेंट्री एलीफेंट व्हिस्पर्स का प्रदर्शन, महाराष्ट्र और हिमाचल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नाटक का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

कार्यशाला के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही ने कहा कि छात्र कल का नहीं, बल्कि आज का नागरिक है और पर्यावरण जैसे आज के जरूरी विषयों

पर इस तरह के सृष्टि मंथन आयोजित करना इस बात का प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता का विचार लोगों के मन में लाना ही विकासार्थ विद्यार्थी का कार्य है। रा. स्व. संघ के पर्यावरण गतिविधि संयोजक गोपाल आर्य ने वाटर स्ट्रेस, इको टेररिज्म, वर्चुअल वाटर, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों के कारण और चुनौतियों के विषय में चर्चा की। वहीं आठ वर्षीय पर्यावरण मित्र आदित्य राजे सिंह ने बताया कि कैसे बचपन से परिवार से उन्हें प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा मिली।

सम्मेलन में क्रमशः दो पैनल डिस्कसन भी आयोजित किए गए। पहले पैनल में भारत की पर्यावरणीय समस्याएं उनका प्रभाव और समाधान विषय पर चर्चा की गई, जिसमें भागीरथ ग्राम विकास संस्थान के माध्यम से बायो गैस और आत्मनिर्भर ग्राम के विषय को लेकर काम कर रहे प्रसाद देवधर, सार्थक संस्थान के माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रैगपिकर्स के लिए काम कर रहे इम्तियाज अली, जेएनयूम पर्यावरण विज्ञान विभाग में प्रा.अमित मिश्रा, विकासार्थ विद्यार्थी के संस्थापक तथा आईआईटी मुंबई के प्रध्यापक शिरीष केदार और संयुक्त राष्ट्र में एसडीजी एडवोकेट तथा भावनगर गुजरात में क्लीनिंग के माध्यम से युवाओं को जागृत करने वाले जयदीप जानी का विद्यार्थियों के साथ संवाद हुआ। इस संवाद में पर्यावरणीय विषयों पर काम करने की चुनौतियों के विषय में भी विस्तृत चर्चा हुई। दूसरे पैनल में 'Sustainability - an integral part of indic way of life' विषय पर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के प्राध्यापक चंद्र कुमार सिंह, एनआईटी नागपुर के प्राध्यापक सचिन मंडवगने, पुनीत द्विवेदी व पर्यावरणविद राज मदनकर के साथ विद्यार्थियों का संवाद हुआ।

विकासार्थ विद्यार्थी के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय संयोजक राहुल गौड़ ने बताया कि यह एक



ऐसा मंच है, जहां छात्र कार्यकर्ता, नीति निर्माता, पर्यावरणविद एवं शोधार्थी पर्यावरणीय मुद्दों जैसे-जलवायुसंकट, जैव विविधता संसाधन प्रबंधन आदि पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं और समाधान का मार्ग खोजते हैं। इस कार्यशाला में विकासार्थ विद्यार्थी के कार्य, देश के पर्यावरण स्थिति पर चर्चा तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई।

समापन सत्र में राष्ट्रीय सह संयोजक मयूर जवहेरी

ने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। अभाविप पश्चिम क्षेत्र के संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने संकल्प पत्र के माध्यम से आगामी कार्य की दिशा पर चर्चा की। 'सृष्टि मंथन' के नाम से विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय कार्यशाला व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 1-2 अप्रैल को लखनऊ स्थित डॉ. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें देशभर के 450 से अधिक छात्र, कार्यकर्ता, प्राध्यापक एवं पर्यावरणविद उपस्थित थे। ■

देश की संप्रभुता व एकता सर्वोच्च, खालिस्तान समर्थकों से कड़ाई से निपटे सरकार: अभाविप

31

खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने पंजाब तथा विदेश के कुछ स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर हुई घटनाओं पर आक्रोश प्रकट किया है। अभाविप ने कहा है कि देश की संप्रभुता सर्वोच्च है और राष्ट्र पुनर्निर्माण के पुनीत कार्य में सभी नागरिक एकजुटता से सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऐसे में 'विभाजन की हिंसक विकृति' से पीड़ित खालिस्तान समर्थकों के हिंसापूर्ण तथा विभाजनकारी कुत्सित एजेंडे का कड़ा प्रतिकार अत्यावश्यक है।

विभिन्न अवसरों पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा लगातार देशविरोधी कृत्य किए जा रहे हैं। पिछले दिनों लंदन में भारतीय झंडे का अपमान किया गया। अनेकों बार देश की महान स्वतंत्रता के लिए वीरगति हो चुके भगत सिंह जैसे अमर बलिदानियों के आहुति का अपमान, देश की संप्रभुता तथा पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। अभाविप ने कहा है कि खालिस्तान की मांग से जुड़े विभिन्न संगठन आईएसआई तथा अन्य भारत विरोधियों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, यह बात अब छिपी नहीं रही। खालिस्तान की आड़ में सिख युवकों को दिग्भ्रमित कर अपनी असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित करने के प्रयासों के कारण देश के बहादुर सिखों को भी कलंकित करने

के असफल प्रयास हो रहे हैं।

वर्तमान भारत में नई संभावनाओं तथा समृद्धि के नए सूत्रों का उद्घाटन हो रहा है तथा वैश्विक पटल पर देश की साख में वृद्धि हुई है। ऐसे में भारत विरोधियों की अकुलाहट का कारण स्पष्टतया समझा जा सकता है।

अभाविप के अनुसार देश के युवाओं के लिए संभावनाओं की बेहतर राहों के बीच कुछेक स्थानों पर ड्रग्स तथा मादक पदार्थों द्वारा युवाओं को गलत पथ पर ढकेलने के षड्यंत्र भी उजागर हुए हैं। सरकार तथा समाज को एकसाथ मिलकर खालिस्तानी षड्यंत्रकारियों के कुत्सित प्रयासों को रोकना होगा। आज भारत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, अनेक क्षेत्रों में प्रगति से वैश्विक स्तर पर भारत के मान में वृद्धि हुई है। देश की एकता तथा अखंडता, किसी भी मत-पंथ या संप्रदाय से ऊपर है। भारत में विभिन्न विषमताएं गति से कम हो रही हैं तथा भारतीय पहचान के साथ प्रत्येक नागरिक अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। जो भी बाह्य शक्तियां उभरते भारत के मार्ग में बाधाएं खड़ी करना चाहती हैं, उनके विरोध में हर भारतीय एकजुट है। अभाविप मांग करती है कि खालिस्तान समर्थकों के समूल उन्मूलन की दिशा में शीघ्रता से कार्रवाई हो। ■



सहजता व सौम्यता की प्रतिमूर्ति अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. ओम प्रकाश कोहली

| प्रा. राजकुमार भाटिया |

स

हजता व सौम्यता की प्रतिमूर्ति अखिल भारतीय विधार्थी परिषद (अभाविप) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. ओम प्रकाश कोहली न केवल एक श्रेष्ठतम सामाजिक कार्यकर्ता थे, बल्कि सादगी और निश्चलता के अप्रतिम उदाहरण भी थे। 9 अगस्त 1935 को एक समान्य पंजाबी परिवार में जन्मे कोहली जी का लगभग 88 वर्ष की आयु में 20 फरवरी 2023 को निधन हुआ। उनका शिक्षण दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ तथा उसी में उन्होंने हिंदी विषय के अध्यापक के रूप में कार्य किया।

विद्यार्थी काल में वे अभाविप के कार्यकर्ता बने तथा अपने महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष भी चुने गए। 1960 के दशक में वे विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन डूटा में सक्रिय भूमिका निभाने लगे तथा राष्ट्रवादी विचारों के शिक्षक संगठन एनडीटीएफ की स्थापना में उनकी अग्रणी भूमिका रही। एनडीटीएफ व अभाविप में उनकी सक्रियता रही। जहां 1970 में वे अभाविप दिल्ली प्रदेश के एक वर्ष के लिए अध्यक्ष बने, वहीं विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रतिनिधि के नाते उन्होंने कई चुनाव लड़े। दो बार वे डूटा के अध्यक्ष चुने गए तथा दो बार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद हेतु शिक्षक प्रतिनिधि चुने गए।

अभाविप में जब 1972 में 'केन्द्रीय टीम' की अनौपचारिक रचना प्राप्त हुई तबसे वे उसके सदस्य रहे। 1982 से 1985 के बीच वे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तथा अभाविप में शिक्षा संबंधी चिंतन व प्रस्तावों, साहित्य आदि का लेखन उनका प्रमुख दायित्व रहा। साथ ही साथ वे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अति सम्मानित शिक्षक नेता के रूप में भी उभरे। 1991 के प्रारंभ में उनके जीवन में एक अनपेक्षित मोड़ आया जब उनकी प्रतिभा का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तथा उन्हें दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया। आगे का उनका तीन

दशकों का जीवन भाजपा के इर्द-गिर्द चला। 1994 में राज्यसभा सदस्य बने, लगभग 14 वर्ष उन्हें भाजपा में कई दायित्व मिले तथा वर्ष 2014 में उन्हें गुजरात का राज्यपाल बनाया गया।

रा.स्व.संघ, अभाविप व भाजपा के वे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने किसी भी दायित्व को अस्वीकार नहीं किया। प्रामाणिक व परिश्रमी होने के कारण उन्हें तदनु रूप दायित्व भी मिलते रहे। कोहली जी एक अध्ययनशील व विद्वान व्यक्ति थे। हिंदी के प्राध्यापक होने के नाते हिंदी साहित्य का अध्ययन उनकी विशेषता थी। राजनीति की चकाचौंध ने कोहली जी को कतई प्रभावित नहीं किया।

स्व. ओम प्रकाश कोहली जी एक अध्ययनशील व विद्वान व्यक्ति थे। हिंदी के प्राध्यापक होने के नाते हिंदी साहित्य का अध्ययन उनकी विशेषता थी। राजनीति की चकाचौंध ने कोहली जी को कतई प्रभावित नहीं किया। जनता व कार्यकर्ताओं के लिए वे सहज-सुलभ नेता थे। राज्यपाल के कार्यकाल में वे राजभवन के कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालते थे। उनकी सादगी अद्वितीय थी।

जनता व कार्यकर्ताओं के लिए वे सहज-सुलभ नेता थे। राज्यपाल के कार्यकाल में वे राजभवन के कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालते थे। उनकी सादगी अद्वितीय थी। पहनावा हो अथवा घर का रख-रखाव ऐसा लगता ही नहीं था कि वे बड़े राजनीतिक नेता हों। दिल्ली में जब शिक्षकों की एक सोसाइटी में घर



बनाने का उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने सबसे छोटा घर लिया, जो बाद में उन्हें बहुत छोटा पड़ गया। राज्यसभा सदस्य के नाते उन्हें नई दिल्ली में सरकारी मकान मिला पर वे उसमें नहीं रहे। वे किसी भी दायित्व पर रहे हों, उनका घर कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था। घर आने वालों की उनसे भेंट तो होती ही थी, प्रायः उन्हें चाय-भोजन भी मिलता था।

कोहली जी की निश्चलता व सहजता आश्चर्यजनक व अविश्वसनीय थी। 1975 में देश में लागू हुए आपातकाल के प्रारंभ में ही वे गिरफ्तार हो गए तथा पूरे 19 मास मीसाबंदी में रहे। यद्यपि ऐसे अनेक संकेत थे कि वे गिरफ्तारी से बच सकते थे पर उनकी अति सज्जनता

ने उन्हें बंदी बना दिया, पर गिरफ्तारी के पश्चात वे निडर रहे तथा पुलिस ने उन्हें पीटा भी और उन पर झूठा मुकदमा बनाया। लेकिन वे अपने साहस से नहीं डिगे। यह भी एक विचित्र संयोग हुआ कि अभावपि के तत्कालीन संगठन मंत्री मा. मदनदास जी को भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा क्योंकि वे भी कोहली जी के साथ थे। यद्यपि कोहली जी ने अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा निभाया परंतु पारिवारिक दायित्वों की भी अनदेखी नहीं की। परिवार में बच्चों के साथ घुलमिल जाना उनकी बाल सुलभ विशेषता थी। उनकी स्मृति को मेरा शत-शत नमन। ■

(लेखक अभावपि के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

SHoDH Delhi organized a lecture on Changing contours of multilateralism in JNU



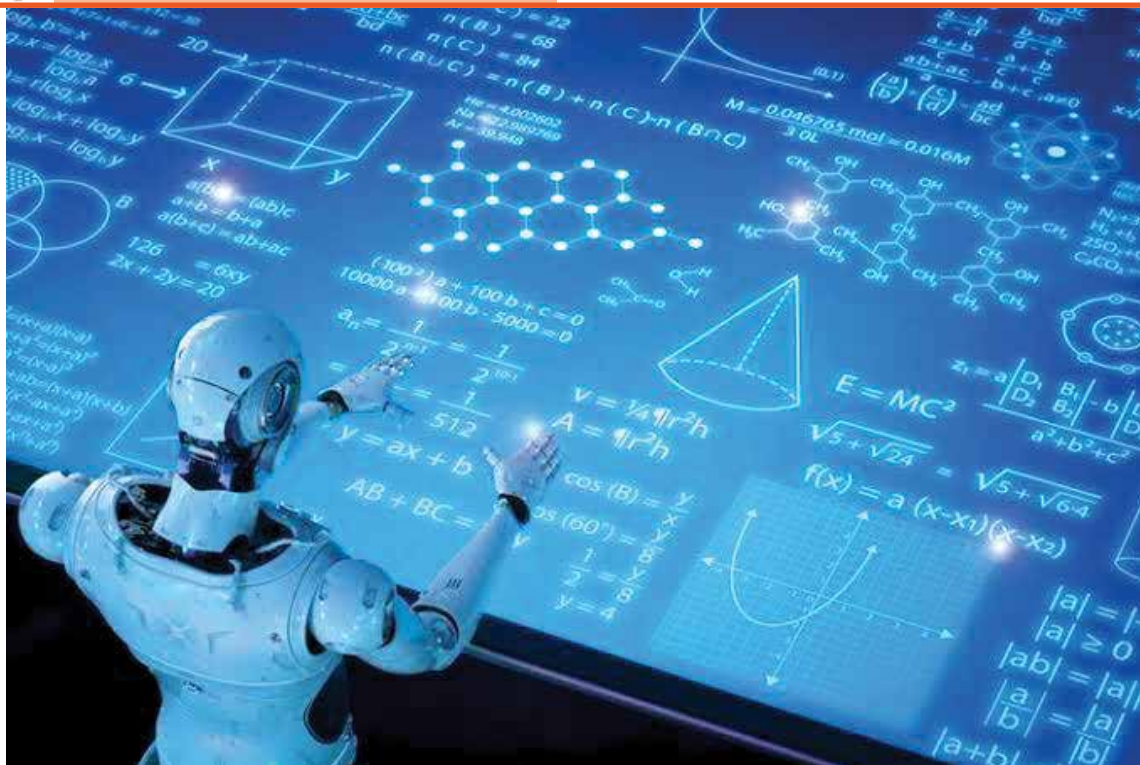
SHoDH JNU organized a highly interactive talk session on, “Changing contours of multilateralism: Challenges and Opportunities”. The main speaker was Hiroyuki Ito, a Project Manager for Green City Action Plan, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). The session was chaired by Professor Shrabani Roy Choudhary, a faculty member at the Centre for East Asian Studies, SIS, JNU.

Mr. Ito discussed in detail the functioning of EBRD and the close-door politics fundamental to multilateral institutions. The talk focused more on the contemporary issues facing humankind, such as climate change, Urban planning, environmental planning, and sustainability concerning the functioning of regional organizations and non-state actors. He emphasized on the fact that how the cooperative arrangement between civil society, the private sector, and State, in general, is essential for tackling contemporary global issues facing humankind. Regarding EBRD, he shared with the audience the internal perspectives, mostly not mentioned in mainstream academia and media.

Therefore, his talk gave the student an idea about how with the help of monetary support, developed countries influenced the financing of multilateral arrangements and how developed nations have the upper hand over the policies and decisions of the international institutions. However, at the same time, the expansionary vision of EBRD to the third-world countries, especially in infrastructural development areas, mitigating impacts of climate change and migration in particular, has been effectively dealt with EBRD.

He said, “As the world is becoming multilateral, we need to innovate a more democratic and fair system. India has an important role to play given its democratic outlook and its large economy.”

At the event, the national convener of SHoDH, Shashank Tiwari, Delhi Convener SHoDH, Prashant Shahi, JNU’s faculty from the School of Disaster Management, Abhijeet Dwivedi were present. The session show a rich participation from various departments of the University. The audience took a huge interest in the discussion and participated in the question session with productive curiosity. ■



Artificial Intelligence (AI) The Way Forward

| Dr. Punit Kumar Dwivedi |

Artificial Intelligence (AI) is transforming the world at an unprecedented pace. It is revolutionizing multiple industries, including healthcare, finance, transportation, and education, to name a few. AI-powered machines are capable of processing vast amounts of data, identifying patterns, and making decisions based on a variety of parameters. These machines are designed to learn from experience and improve their performance over time. In this paper, we will analyze the impact of AI

on different areas of our lives, including education, society, innovation and startups, employment generation, business, healthcare and agriculture.

AI and Education:

AI is quickly becoming an essential tool in the education sector. Teachers can use AI-powered software to develop customized learning programs for students. This means that students can learn at their own pace and receive individualized attention. AI can also help teachers assess student progress more accurately by analyzing data on their behavior, engagement, and performance. This data can help teachers identify areas where students need assistance and adjust



their teaching methods accordingly.

Moreover, AI-powered software is also a valuable tool for educational research. Researchers can use AI to analyze large amounts of data on student behavior, test scores, and other factors that may impact learning outcomes. This data can help policymakers develop evidence-based policies to improve educational outcomes.

AI and Society:

AI is rapidly transforming the way we live and interact with each other. It is powering a wide range of products and services, from virtual assistants to autonomous vehicles. However, there are concerns that AI may also have negative impacts on society, such as increased inequality and job displacement.

One of the most significant concerns is the potential impact of AI on employment. AI-powered machines are expected to replace many jobs that are currently performed by humans, including drivers, retail workers, and factory workers. This could lead to significant job displacement, particularly for low-skilled workers.

Another concern is the potential for AI to reinforce existing inequalities. For instance, AI algorithms may be biased against certain groups, such as women or people of color. There is also a risk that AI-powered machines may be used to promote harmful practices, such as surveillance or discrimination.

AI and Innovation & Startups:

AI is driving innovation across multiple industries, including manufacturing, healthcare, and finance. Startups are also using AI to develop new products and services that are more efficient, cost-effective, and personalized.

AI-powered startups are disrupting traditional business models by leveraging data to deliver insights and solutions that are faster and more accurate. For instance, AI-powered financial services are providing customers with personalized investment

strategies based on their risk tolerance, goals, and other factors.

Moreover, AI is also being used to improve research and development processes, by identifying new opportunities and predicting market trends. AI-powered startups are also developing innovative solutions to some of the world's most pressing challenges, such as climate change and healthcare.

AI and Employment Generation:

While AI has the potential to displace many jobs, it is also creating new employment opportunities. AI-powered machines require skilled technicians, engineers, and data scientists to design, develop and maintain them. Moreover, AI is also driving demand for jobs in new fields, such as robotics, automation, and natural language processing.

There is also a growing demand for workers with AI-related skills. This includes workers who can develop and manage AI systems, as well as those who can work collaboratively with machines. To meet this growing demand, education and training programs are needed to develop the required technical and soft skills.

AI and Business:

AI is transforming the way businesses operate by providing insights and solutions that enable them to make better decisions, streamline operations, and improve customer experiences. AI-powered solutions are helping businesses to optimize supply chains, manage inventory, and develop more effective marketing strategies.

Moreover, AI is also being used to develop new business models. For instance, AI-powered platforms are enabling businesses to leverage data to create new revenue streams, such as subscription-based services or pay-per-click advertising.

AI APPLICATIONS IN MEDICAL DIAGNOSIS:

Machine learning algorithms have enabled computers to analyze vast amounts of data



efficiently and accurately, including patient records, images, and genomic data, leading to better medical decisions. With the help of AI, top pharmaceutical and biotech companies are discovering new drugs and therapies, diagnosing diseases earlier, and delivering treatments with higher precision and lower side-effects.

In the case of cancer diagnosis, image recognition software is used to analyze pathology images and identify cancerous cells, providing a more robust and accurate diagnosis. AI is also used to detect other diseases, such as heart disease and stroke, with high levels of accuracy.

Role of AI in Medical Research:

AI-based research tools have made analyzing medical data much quicker and more efficient than traditional methods. AI algorithms have the ability to work 24/7, continuously analyzing and discovering patterns across large data sets. AI is also being used to predict disease outbreaks and track their spread, aiding in early detection and response.

AI APPLICATIONS IN HEALTHCARE ADMINISTRATION:

AI is being used in healthcare systems to help hospitals, clinics, and other medical facilities operate more efficiently, increasing patient care outcomes, and reducing costs. AI chatbots are developed to act as medical assistants and accommodate patients with necessary information about medical procedures and medicines that can help. AI systems are also used to generate predictive models for staff allocation and resource management.

AI Applications in Agriculture:

1. Crop monitoring

One of the significant applications of AI in agriculture is crop monitoring. Farmers can use AI-powered drones and sensors to monitor crops from the air and on the ground. Drones equipped with high-resolution cameras and sensors can help identify crop stress and

early signs of disease or pest infestations.

2. Precision farming

Precision farming is another significant application of AI in agriculture. It involves using data, sensors, and AI algorithms to optimize crop yield and reduce waste. AI algorithms can help farmers identify the correct time to plant crops, optimize water usage, and apply pesticides and herbicides to reduce waste and ensure that only the necessary amount is used.

3. Predictive Analytics

Data analytics and predictive modeling allow farmers to make informed decisions about crop management by predicting outcomes for specific conditions. AI software can collect data about weather, soil quality, and other critical factors that affect crop growth and development. Predictive modeling can then provide farmers with an analysis of which crops will be most successful under certain circumstances.

4. Crop Yield Estimation

AI can help farmers estimate crop yields by analyzing historical data and current growing conditions. This allows them to make informed decisions about when to plant and harvest crops. AI algorithms can also analyze soil and weather data and provide recommendations on which crops are likely to perform best.

Conclusion:

AI is a powerful technology that is transforming the world in many ways. It has the potential to improve educational outcomes, drive innovation, and create new jobs and business models. However, it is also important to be aware of the potential negative impacts of AI on society, such as increased inequality and job displacement. To ensure that AI is used in a responsible and ethical manner, it is essential to develop policies and regulations that balance the benefits of AI with its potential risks. ■

(Author is Chief Advisor & Mentor of Modern Incubator (Supported by MSME, GoI))



प्राध्यापक व नॉन टीचिंग स्टाफ के रिक्त पदों को अविलंब भरे बिहार सरकार : अभाविप



हार में प्राध्यापकों एवं नॉन टीचिंग स्टाफों की कमी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से बहाली करने की मांग की है। अभाविप, बिहार ने 12 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है और कहा है कि शिक्षा की सुरभि का केंद्र रहा बिहार अब सरकार की उदासीन एवं अकर्मण्य रवैये के कारण अस्त-व्यस्त व त्रस्त है। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों तथा कर्मचारियों की घोर कमी है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 55 प्रतिशत और कर्मचारियों के 56 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

40 वर्षों से रीडर व प्रोफेसरों की नियुक्ति का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही आधारभूत संरचना प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दयनीय है। दसों विश्वविद्यालयों में कुल 7614 सृजित पदों में 4179 पद शिक्षकों के पद रिक्त है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन तो कर दिया गया लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गयी है कि 3 वर्ष से अब तक साक्षात्कार ही चल रहे हैं। इस कारण 4638 पदों पर होने वाली नियुक्ति में केवल डेढ़ सौ पद को साक्षात्कार द्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोग भर पाया है, वह भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गयी है।

बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होने वाली नामांकन व परीक्षा की प्रक्रिया जानबूझकर दलालों और शिक्षा माफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य धीमी गति से चल रही है। प्रवेश परीक्षाओं सहित परीक्षाओं, परिणाम प्रकाशन, वर्ग संचालन की स्थिति भी निराशाजनक है। कई विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक महीने में केवल 2 दिन आकर अन्य दिनों की अनैतिक उपस्थिति बनाकर वेतन ले रहे हैं। इस प्रक्रिया को विकसित कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा मोटी रकम वसूली जा रही है। शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी का परिणाम है कि नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी का बनाये रखा गया है, ताकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय

में मनमानी कर सके। बिहार के विश्वविद्यालयों में 4461 पद शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के रिक्त हैं, जिन पर अब तक नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।

अभाविप के प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान सरकार व विश्वविद्यालय सेवा आयोग मृतप्राय बनाने पर आमादा है। उन्होंने शैक्षिक व्यवस्था पर क्षोभ व्यक्त करते हुए शिक्षकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने व विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना को अविलंब दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही विश्वविद्यालय सेवा आयोग बिहार से शैक्षिक व गैर शैक्षिक नियुक्ति अविलंब पुनः प्रारंभ करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभाविप आंदोलन करने को बाध्य होगी। ■

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अप्रैल 2023 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वपूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें :-

‘राष्ट्रीय छात्रशक्ति’

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नयी दिल्ली - 110002.

फोन : 011-23216298

www.chhatrashakti.in

✉ rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com

📘 www.facebook.com/Rchhatrashakti

🐦 www.twitter.com/Rchhatrashakti

📷 www.instagram.com/Rehhatrashakti

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा



गुवाहाटी : उद्घाटन समारोह को संबोधित करते अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत



एकात्म यात्री को सम्मानित करते गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत



कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के साथ एकात्म यात्री



जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एकात्म यात्री

2023 की झलकियां



नागपुर में रा.स्व.संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ एकात्म यात्री



धर्मशाला में दलाईलामा के साथ एकात्म यात्री



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एकात्म यात्री



गोरखपुर में गीत प्रेस का भ्रमण करते एकात्म यात्री



नागरिक अभिनंदन समारोह में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, सील अध्यक्ष अतुल कुलकर्णी व अन्य



बीकानेर में ऊंट की सवारी करते एकात्म यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्र

राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा



मुंबई : अभिनेता अनुपम खैर एवं अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ एकात्म यात्री



रांची : पद्मश्री अशोक भगत के साथ एकात्म यात्री



विशाखापट्टनम : एकात्म यात्रियों को तटरक्षा के बारे में बताते अधिकारी



मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि दर्शनोपरांत एकात्म यात्रियों की सामूहिक छायाचित्र



पुदुचेरी के उपराज्यपाल टी. सौंदराजन के साथ एकात्म यात्री

A-2023 की झलकियां



अयोध्या : निर्माणाधीन राम मंदिर को देखने गए पूर्वोत्तर छात्रों का सामूहिक छायाचित्र



स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गए पूर्वोत्तर छात्रों का सामूहिक छायाचित्र



देहरादून : एकात्म यात्री को सम्मानित करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी



दिल्ली : केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ एकात्म यात्री



दिल्ली का विश्वस्तरीय (अ) शिक्षा मॉडल...!

| अभिषेक रंजन |

कि

सी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ ही राष्ट्र के विकास और भविष्य का निर्धारण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके विपरीत यदि शिक्षा व्यवस्था दूषित होकर मात्र खोखले दावों का कारण बनती है तो ऐसे राष्ट्र या समाज में नकारात्मकता हावी होती है और यह नकारात्मकता अव्यवस्था और विनाश की ओर ले जाती है।

कुछ ऐसा ही भारत की राजधानी दिल्ली में देखा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ स्वयं थपथपाती हुई, पिछले कई वर्षों से विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था का ढोल पीटती आ रही है। मीडिया में बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के विश्वस्तरीय होने का दावा लगातार किया जा रहा है। प्रचार की रणनीति के तहत विश्वस्तरीय नेताओं को दिल्ली सरकार से सम्बंधित स्कूलों में ले जाकर ऐसा बताया जा रहा है कि देश में एकमात्र दिल्ली सरकार ही ऐसी सरकार है, जो शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है और शिक्षा व्यवस्था को छात्रों के अनुकूल बनाकर उनके भविष्य को संवारने का कार्य कर रही है। यह एक पक्ष है। अब इसके दूसरे पक्ष पर ध्यान देते हैं।

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित होता है कि राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं और 11वीं के छात्रों की बड़ी संख्या परीक्षा पास करने में असफल हुई। गत 31 मार्च को आए परिणाम के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर छात्रों के अंकों में सुधार करने का समय दिया। इस समाचार का हैरतअंगोज पहलू यह भी है कि जिन स्कूलों में 9वीं और 11वीं के परिणाम ज्यादा खराब हुए हैं, उन स्कूलों के प्रधानाचार्य अपने शिक्षकों पर छात्रों की कापियों में सही उत्तर लिखकर दोबारा कापी जांच कर उनको पास करने का दबाव बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली की विश्वस्तरीय शिक्षा

व्यवस्था के “सच” को सामने उजागर करते हुए अबकी बार के परिणाम में 96 प्रतिशत से अधिक छात्र फेल हुए हैं। 60 बच्चों की कक्षा में केवल चार से पांच बच्चे ही पास हुए हैं। परीक्षा के दौरान कई छात्रों ने उत्तरपुस्तिका के पन्नों को खाली छोड़ दिया तो कई छात्रों ने उत्तर गलत लिखे। अब दिल्ली का शिक्षा निदेशालय यह प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह इन सभी बच्चों को पास कर दिया जाए और इसके लिए शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह बच्चों की उत्तर पुस्तिका में यथोचित सुधार करें।

प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ ? या दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है ? उत्तर भी दिल्ली सरकार की कार्य प्रक्रिया पर कई प्रश्न उठाने के लिए काफी है। दिल्ली में आप सरकार ने पिछले वर्ष तक आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए नो डिटेन्शन नीति को लागू किया था। इस नीति के अंतर्गत किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था। इस अविवेकपूर्ण नीति के कारण सभी छात्रों को बिना किसी वास्तविक परीक्षण के स्थान पर पास करके 9वीं कक्षा में भेज दिया गया और अब यही छात्र फेल हो रहे हैं। इस प्रकार हम देखें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था के नाम पर छात्रों और अभिभावकों की आंखों में धूल झाँकने का कार्य कर रही है। यह सरकार कितनी जिम्मेदार है, यह इसी से समझा जा सकता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बताकर प्रचार करने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री जेल में हैं क्योंकि शिक्षा के साथ ही वह राज्य के आबकारी मंत्री के पद को भी संभाल रहे थे और आबकारी मंत्री के रूप में किये गए घोटाले के कारण वह जेल जाकर जांच का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के नाम पर किस तरह से जनता की आंख में धूल झाँकी है, यह समझना भी कोई जटिल कार्य नहीं है।

2015 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के कई सारे वादे दिल्ली की जनता से किए थे। इन वादों में 500 नए स्कूल खोलने, 17 हजार शिक्षकों की बहाली और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना शामिल था। पार्टी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में ‘सबको मिली अच्छी शिक्षा’ के दावे किये और शिक्षा



बजट को तीन गुना बढ़ाने, नए कमरे बनाने और बारहवीं के रिजल्ट बेहतर होने को अपनी उपलब्धि बताया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

देशभर में 12 लाख से अधिक सरकारी स्कूल चलते हैं। जबकि दिल्ली सरकार के पास महज हजार स्कूल हैं। पिछले छह वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार के दावों के विपरीत शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों ने महसूस किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल सीखने की जगह के स्थान पर राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। पढ़ने-पढ़ाने के वातावरण वाले लोगों की बजाए दिल्ली में भव्य इमारत को ही शिक्षा की पहचान बनाया गया। बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी करें, उससे अधिक चिंता येन-केन-प्रकारेण परीक्षा परिणाम बेहतर करने की होने लगी। स्कूल परिसर शिक्षा केंद्र बनने के स्थान पर राजनीतिक आयोजनों का अड्डा बन गए। वर्ष 2017 से लगातार दिल्ली की शिक्षा में हो रहे काम का अवलोकन करने और दिल्ली के कई स्कूलों, शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों से बात करने से हमेशा लगा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर एक स्वस्थ बहस अवश्य होनी चाहिए।

प्रशासनिक दृष्टि से देखे तो राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में मुख्य रूप से केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल शामिल हैं। इनमें से दिल्ली सरकार के अधीन 1030 सरकारी स्कूल आते हैं। इसी प्रकार नगर निगम के अधीन अभी 1700 स्कूल चलते हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 200 ऐसे स्कूल भी चलते हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राज्य ने एक-चौथाई बजट शिक्षा के लिए आवंटित किया। कई बार दिल्ली के शिक्षा बजट की तुलना एशिया, यूरोप के देशों से भी लोग करते नजर आते हैं। यह सत्य है कि शिक्षा के लिए दिल्ली में अधिक बजट आवंटित हो रहा है, पर यह बजट क्या शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में मदद कर रहा है? नहीं। वास्तविकता तो यह है कि दिल्ली आज भी अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत से भी कम पैसे खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-2020 तक के बजट को देखें तो जहां आवंटन में वृद्धि हुई है, वही यह भी देखा गया है कि आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ। राज्य सरकार की चतुराई पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इस बात के लिए भी आपत्ति व्यक्त की है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति

से पहले यानी आखिरी महीने में बजट की बड़ी राशि खर्च की जाती है।

2015 में दिल्ली में जब नई सरकार बनी तब दिल्ली सरकार के पास 1007 सरकारी स्कूल थे, वही 211 स्कूलों को दिल्ली सरकार वित्तीय सहायता मुहैया कराती थी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की संख्या २२७७ थी। पर जनवरी, 2020 तक के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले स्कूलों की संख्या 1030 है अर्थात् वर्ष 2015 की तुलना में 2020 तक कुल 23 नए स्कूल जुड़े। ज्यादातर बने नए स्कूल वर्ष 2014-15 में स्वीकृत स्कूल ही थे, जिसे राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 जुलाई 2014 को दिल्ली का बजट लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए 22 नए स्कूल बनाने के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। लेकिन सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल, 2015 से लेकर 31 मार्च, 2019 तक केवल एक स्कूल बनाने की स्वीकृति दिल्ली सरकार ने दी।

ऐसा प्रचारित किया जाता रहा है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षा इतनी बेहतर हो गयी कि निजी स्कूलों को छोड़ कर बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़े ही सरकारी प्रचार की पोल खोलते हैं। सच तो यह है कि गत चार वर्षों में ही जहां निजी स्कूलों में ढाई लाख बच्चे बढ़े, वहीं सरकारी में डेढ़ लाख बच्चे घट गए। 2019 में आये दिल्ली के इकॉनॉमिक सर्वे के अनुसार दिल्ली में 2013-14 में 992 सरकारी स्कूल थे, जहां 16 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते थे। 2017-18 तक पिछली सरकारों द्वारा स्वीकृत कुछ नए सरकारी स्कूल बने और स्कूलों की संख्या में 27 का इजाफा हुआ। लेकिन बच्चे घटकर 14 लाख पर आ गए। इसी दौरान 558 निजी स्कूल बंद हुए, इसके बावजूद निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 2013-14 के मुकाबले 2017-18 तक आते-आते 2 लाख 64 हजार बढ़ गए। सरकारी स्कूलों की भारी कमी और लगातार बंद होते कम फीस वाले निजी स्कूलों की वजह से दिल्ली में आज भी हजारों ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूलों की पहुंच से बाहर हैं या फिर ड्रापआउट हो रहे हैं।

प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने वाले बच्चों के अंतरण दर भी दिल्ली के स्कूलों की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक जाते जाते काफी बच्चे कम हो रहे हैं। इसके



दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के 16000 से अधिक पद खाली रहना दिल्ली सरकार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का परिचायक : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दिल्ली में दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 16000 से अधिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों को दिल्ली सरकार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का परिचायक मानती है तथा जल्द से जल्द इन पदों को भरने का आग्रह करती है।

जानकारी हो कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ओर से न्यायालय को जो जानकारी दी गई है, उस जानकारी के अनुसार लाइब्रेरियन को मिलाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53,933 है इनमें से 16,546 पद खाली पड़े हैं। इसमें भी सबसे अधिक टीजीटी के 10,956 पद खाली हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का अपनी शिक्षा व्यवस्था का झूठा गुणगान करना अपनी खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था को छुपाने के लिए है, जिसका अभाविप कड़े शब्दों में निंदा करती है एवं दिल्ली सरकार से मांग करती है कि खाली पड़े शिक्षक के पदों को जल्द से जल्द भरे जाए।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि हाल ही में शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए शिक्षकों के पदों की रिक्तियां दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था का सच सामने लाती हैं। दिल्ली सरकार गत कई वर्षों से दिल्ली की जनता को ऐसे ही मूर्ख बनाती रही है। इनके विश्वविद्यालय तथा स्कूल कागजों पर तो दिखे परंतु वास्तविकता में नहीं हैं। अभाविप दिल्ली सरकार से मांग करती है कि दिल्ली सरकार अपने झूठे कागजी हथकंडों पर से ध्यान हटाकर वास्तविकता पर काम करे एवं दिल्ली में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को जल्दी से भरे।

साथ ही बच्चों के सीखने का स्तर भी बदहाल है। गत 5 वर्ष में दिल्ली के बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए कई प्रयास करने का दावा किया गया, जिनमें मिशन

चुनौती व मिशन बुनियाद प्रमुख है। मिशन चुनौती अपने उद्देश्यों में अधिक सफल नहीं हुआ और 9वीं में ड्रापआउट की संख्या शून्य करने में सफलता नहीं मिली। सुधार के दावों के बावजूद पिछले 2 वर्षों के आंकड़े देखे तो लगभग 42 प्रतिशत बच्चे 9वीं में फेल हुए। फेल बच्चों के आंकड़े भी आप सरकार ने भारी जनदबाव के बाद जारी किए। इसी प्रकार मिशन बुनियाद भी कोई खास सफलता नहीं हासिल कर पाया। दिल्ली में लाखों बच्चों के पास अभी भी भाषा और गणित की शुरुआती दक्षतायें नहीं हैं। दिल्ली की आबादी कम नहीं हुई, इसके बावजूद 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे लगातार कम क्यों हुए? शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग घटती संख्या के पीछे बड़ी संख्या में 9वीं की परीक्षा में बच्चों को स्कूलों में फेल करके बाहर निकालने की नीति को जिम्मेवार मानते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं में बड़ी संख्या में बच्चे फेल तो हो ही रहे हैं, फेल होने के बाद उन्हें पुनः स्कूल में नामांकन न देने की अघोषित नीति भी स्कूली शिक्षा से लाखों बच्चों को वंचित कर रही है।

दिल्ली में आज भी सभी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली के स्कूलों में कंप्यूटर लेकर पढ़ने और 12वीं की परीक्षा कंप्यूटर साइंस विषय लेकर देने वाले बच्चों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है और बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार अपने मात्र आठ स्कूलों की तस्वीर ही मीडिया अथवा सोशल मीडिया में दिखा कर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्वस्तरीय बना देने का दावा करती है। दिल्ली में जब आप पार्टी की सरकार बनी तो केवल 5 प्रतिशत अच्छे स्कूलों को छांटा गया, उन्हीं पर ध्यान दिया गया। एक हजार में से केवल 54 स्कूल चुने गए, उन्हें मॉडल स्कूल का नाम दिया। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि अभी भी आधे स्कूलों में ही काम पूरा हो सका। इसके साथ तथ्य यह भी है कि जहां काम हुए वहां कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं।

दिल्ली सरकार चाहे जितने भी दावे करे लेकिन सच यह है कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा देने का काम 5-10 प्रतिशत बच्चों तक ही हो पाया। बाकी 90-95 प्रतिशत बच्चों को अगर शिक्षा देने का काम हुआ भी तो वह बेहद काम चलाऊ तरीके से और खानापूर्ति के लिए ही हुआ। दिल्ली सरकार के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है कि आखिर बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं? नामांकन क्यों घट रहे हैं? परिणाम क्यों



बिगड़ते जा रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं बढ़े, विज्ञान की पढ़ाई महज 7 फीसदी बच्चों तक क्यों सिमट कर रह गयी? एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चर्चा जोरों पर है तो दिल्ली में शिक्षा स्तर की जटिल खामियों के कारण लाखों बच्चे हर वर्ष शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जिस तरह

लाखों गरीब बच्चों को फेल किया गया, उन्हें स्कूलों से शिक्षा क्रांति के नाम पर चुपचाप निकाल दिया गया, वह आंख खोलने के लिए काफी है। कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक पैतरेबाजी की आड़ में दिल्ली के गरीब लोगों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा एक स्वप्न बन चुकी है। ■

वैज्ञानिक व तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ पाठ्यक्रमों में सुधार आवश्यक: अभाविप

रा

ष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की ओर से दसवीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए इतिहास की पुस्तकों का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी घोषणा पिछले साल जून में ही कर दी गई थी वहीं उत्तर प्रदेश ने इन बदलावों को लागू भी कर दिया है। एनसीईआरटी के इस बदलाव के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने पूरे विवाद पर कहा है कि मुगलों के बारे में अध्याय नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने कहा, 'यह झूठ है। पिछले साल एक सुव्यवस्थीकरण प्रक्रिया (रेशनलाइजेशन प्रोसेस) थी क्योंकि कोरोना के कारण हर जगह छात्रों पर दबाव था। उन्होंने बहस को अनावश्यक बताते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि यदि अध्याय को हटा दिया जाता है तो इससे बच्चों के ज्ञान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक अनावश्यक बोझ को हटाया जा सकता है।

वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस प्रकरण पर अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम वैज्ञानिक, तर्कसंगत तथा समग्रता की दृष्टि से युक्त होने चाहिए। देश की शिक्षा व्यवस्था को वामपंथियों तथा तथाकथित पंथनिरपेक्षतावादियों ने लंबे समय तक खंडित, एकपक्षीय तथा एजेंडा चलाने के शस्त्र के तौर पर देखा, जिससे इतिहास सहित कुछ विषयों के पाठ्यक्रम छात्रों के समग्र विकास का स्पष्ट खाका होने के स्थान पर दोष व विवाद का समय-समय पर माध्यम बने और इससे शिक्षा व्यवस्था को नुकसान हुआ।

अभाविप के अनुसार देश का इतिहास केवल दिल्ली केन्द्रित

या मध्यकाल के कुछेक शासक वंशों तक ही केन्द्रित कर देखने की परिपाटी को मिटाकर, समग्र तथा सभी पक्षों को समेकित किए हुए नई परिपाटी गढ़ा जाना समय की मांग है। अहोम, चोल, विजयनगर, गोंड आदि राजवंशों के इतिहास सहित जनजातियों के गौरवशाली इतिहास का पाठ्यक्रमों में समुचित स्थान सुनिश्चित करना चाहिए।

विद्यार्थियों में तथ्य व समग्रता आधारित दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टि के विकास तथा इक्कीसवीं सदी के कृत्रिम मेधा के व्यापक परिवर्तनकारी दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर नए पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा इस दिशा में कदम बढ़ाने से शिक्षा क्षेत्र में आज की आवश्यकता अनुरूप बदलाव किए जाने की आशाओं को उचित स्वर मिला है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि भारतीय इतिहास को समग्रता से पढ़ाया जाना चाहिए, न कि उसे केवल दिल्ली केन्द्रित या केवल एक सल्तनत के शासनकाल के एक ही पक्ष तक केन्द्रित किया जाना चाहिए। पूर्व में ऐसा करके तथाकथित बुद्धिजीवियों ने देश की आशाओं तथा इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। देश की शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों का अद्यतन किया जाना तथा पूर्व में हुई भूलों को सुधारा जाना बहुत आवश्यक हो गया है। एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस दिशा में उचित प्रयास हो रहे हैं। वामपंथियों सहित अन्य एजेंडावादियों को हर बदलाव को अपने चश्मे से देखने की पुरानी गलत आदत बदलनी होगी। पाठ्यक्रमों में सुधार तथा समग्रता निहित किया जाना आवश्यक है। ■



बिहार में नियमों से समझौता कर नियुक्त कुलसचिवों को पदमुक्त किए जाने का निर्णय स्वागतयोग्य: अभाविप



हार के नवनियुक्त राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में आ गये। उन्होंने नियम – कानून को ताक पर रखकर पूर्व तिथि में नियुक्त किए गए आठ कुलसचिवों को पदमुक्त कर दिया है। अभाविप ने कुलाधिपति के इस निर्णय का स्वागत किया है। अभाविप ने 13 मार्च को जारी किए अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बिहार प्रदेश में नियमों से समझौता कर पूर्व-तिथि में नियुक्त किए गए आठ कुलसचिवों को पदमुक्त कर कुलाधिपति ने शैक्षणिक तथा प्रशासनिक हित में निर्णय लिया है। अभाविप ने बिहार में शैक्षिक अव्यवस्थाओं तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बिहार के वर्तमान राज्यपाल से गत फरवरी माह में हुई शुभेच्छा भेंट में अनुरोध किया था कि बिहार की पूर्ववर्ती व्यवस्था द्वारा कई उच्च शिक्षण संस्थानों के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां अत्यंत हड़बड़ी में की गईं, ऐसे में इन नियुक्तियों को लेकर प्रबुद्ध

समाज में विभिन्न शंकाएं थीं।

बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति दयनीय है, जिसको ठीक करने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। अभाविप ने बिहार राज्यपाल से मिलकर कुलसचिवों की नियुक्तियों में नियम के साथ समझौता करने के बारे में अवगत कराया था, राजभवन द्वारा ऐसे कुलसचिवों को हटाए जाने के निर्णय का स्वागत है। अभाविप मांग करती है कि बिहार में शिक्षा क्षेत्र को बेहतर करने की दिशा में सरकार तेजी से प्रयास करे।

बिहार में दो से अधिक वर्ष की देरी से चल रहे कई विश्वविद्यालयों के सत्र को ठीक करने, आधारभूत संरचना की माली हालत को सुधारने सहित विभिन्न सकारात्मक कदम प्रदेश सरकार को उठाने होंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचारमुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के निमित्त गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। ■

Efforts should be made to create a stress-free positive environment in higher education institutions: ABVP



khil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) demands that efforts should be made to reduce the academic pressure and tensions in all higher education institutions of the country. This major step towards stress free, happy and meaningful student life must be made at both institutional and policy levels. The difficulties that have been created in the life of students by the Covid-19 pandemic and various other reasons are now quite evident.

ABVP demands that in order to remove problems like academic pressure, stress among the students and to achieve the larger goal of stress-free, positive-lively campuses and educational life various new programs and activities should be started in the educational campuses which will ultimately spread positivity among the students. Such programs and activities have become need of the hour to improve the mental health of the students.

In the VicharBaithak of ABVP held in

Tiruchirappalli in the year 2020, ABVP demands to make the campuses 'the center of joyful and meaningful student life and to create a positive environment for the students to get education so that students grow socially and ultimately contribute to the growth of the Nation.

ABVP has a clear view that there is a need to expedite the work in this direction for creating a optimistic environment.

ABVP's National General Secretary Yagyawalkya Shukla said, "The manner in which several incidents of suicide have come to light in different higher education institutions of the country in the past are very worrying. To improve this situation, various positive steps should be taken. In order to reduce academic stress, all stakeholders including the government and heads of educational institutions must come together and make efforts to bring about positive changes in educational campuses and create an open and positive environment for students." ■

अभाविप द्वारा पटना में बिहार मंथन कार्यक्रम का आयोजन

31

खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बिहार द्वारा प्रदेश की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर "बिहार मंथन" कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में व्याप्त समस्याओं को जानना, छात्रों की आ रही परेशानी एवं निदान पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल उपस्थित थे। उन्होंने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ विश्वविद्यालयवार समस्याओं पर चर्चा की एवं आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान अभाविप बिहार प्रांत संगठन मंत्री डॉ. सुग्रीव कुमार एवं राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो. नरेंद्र कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे।

कार्यक्रम में प्रदेश में व्याप्त समस्याओं बिहार के सभी विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, नामांकन में देरी, परीक्षा का आयोजन समय पर नहीं होना, परीक्षा परिणाम प्रकाशन में बड़े पैमाने पर धांधली, इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव, शिक्षक और कर्मचारियों की घोर कमी, छात्रों के अनुपात में उनके लिए छात्रावास का न होना, छात्राओं के लिए घोषित मुफ्त शिक्षा का पैसा महाविद्यालयों को नहीं देना, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में परास्नातक विभाग सभी विषयों का पढ़ाई नहीं होना, शिक्षा शुल्क सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में असंगत रूप से अलग-अलग होना, पुस्तकालय सुचारू रूप से चालू नहीं होना, सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य का नहीं होना, अतिथि शिक्षकों की बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली, विश्वविद्यालय की जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को आधार बनाकर सभी विश्वविद्यालय के जमीन को बिहार सरकार के द्वारा अवैध तरीके से अधिग्रहण करना, छात्रसंघ चुनाव

समय पर नहीं होना, वोकेशनल कोर्स के शुल्क में असमान रूप से वृद्धि, सभी विश्वविद्यालय के बंद पड़े प्रेस, निजी महाविद्यालयों की मनमानी, गृह जिला के अलावा अन्य जिलों में परीक्षा केंद्रों का होना, इंटरनेशनल और प्लेसमेंट सेल का ना होना, दूर शिक्षा निदेशालय का बंद होना, डिस्पेंसरी का अभाव इत्यादि विषय पर गहन रूप से मंथन किया गया।

इस मंथन के बाद अभाविप बिहार प्रदेश ने तय किया कि आने वाले समय में इन सभी विषयों को लेकर अभाविप के कार्यकर्ता पूरे बिहार भर में चरणबद्ध तरीके



से आंदोलन चलाएंगे तथा इसके समाधान हेतु राज्यपाल महोदय, संबंधित विभाग और अधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि इसके बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ बिहार की राजधानी पटना में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन पटना के ए.एन. सिन्हा संस्थान में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ममता कुमारी, प्रांत संगठन मंत्री डॉ. सुग्रीव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपरोक्त के अलावा बिहार प्रांत के प्रांत सह संगठन मंत्री धीरज कुमार, रौशन कुमार और केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य नीतीश कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ■

उत्तर प्रदेश में बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने के निर्णय का अभाविप ने किया स्वागत

बे

टियों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सरकार दो लाख से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक अप्रैल को आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत 45 हजार से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली 11 से 14 साल तक की लाखों छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों एवं कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को दिया जाएगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किए जाने के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एक विराट स्वरूप ले रहा है, जिसको सरकार के इस पहले से बल मिलेगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के 45 हजार से अधिक विद्यालयों में अध्ययनरत दो लाख से भी अधिक छात्राओं को

आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें आत्मरक्षा के महत्व को भी समझाया जाएगा। प्रशिक्षण सत्र के साथ ही उन्हें विभिन्न सामूहिक चर्चा के माध्यम से ईव टीजिंग, साइबर बुलिंग, एसिड हमला जैसे विषयों पर भी जागरूकता प्रदान की जाएगी।

अभाविप राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं प्रगति कर रही हैं, उनकी

इस बढ़ती सहभागिता के साकारात्मक परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय महिलाओं को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अभाविप यह आशा करती है कि प्रदेश सरकार के साथ जो अन्य हितधारक हैं वह भी इस दिशा में पहल करेंगे, जिससे छात्राओं को हर संभव तरीके से सशक्त किया जा सके।

अभाविप द्वारा 'मिशन साहसी' के माध्यम से छात्राओं को कई वर्षों से दिया जा रहा है आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के निर्णय का चहुं ओर स्वागत किया जा



रहा है परंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से पहले की इस पर काम कर रही है। अभाविप मिशन साहसी अभियान के माध्यम से विगत कई वर्षों से छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर रही है। अभाविप द्वारा मिशन साहसी के तहत देश भर में लाखों की संख्या में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाये जा चुके हैं। ■



देश के हर जिले में खुले मेडिकल महाविद्यालय: अभाविप

दे

शहर में सरकारी मेडिकल महाविद्यालय और महाविद्यालय में एमबीबीएस की सीटों में साल 2014 के बाद बेतहाशा वृद्धि हुई है। आठ साल में जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 71 प्रतिशत तक बढ़ी है। वहीं, एमबीबीएस की सीटों में 97 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसकी जानकारी सरकार ने संसद में बजट सत्र के दौरान दी है। मेडिकल महाविद्यालयों की वृद्धि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने व्यक्त करते हुए कहा है कि पिछले वर्षों में विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों में बड़ी संख्या मेडिकल छात्रों की रही है, ऐसे में वर्ष 2014 की तुलना में अब देश के मेडिकल क्षेत्र के आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में प्रगति के साथ मेडिकल सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि का अभाविप ने स्वागत करती है साथ ही देश के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र का व्यापक विस्तार किए जाने की दिशा में शीघ्रता से प्रयास किए जाने की मांग भी की है। अभाविप ने कहा है कि वर्तमान में मेडिकल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने नितांत आवश्यक हैं।

देश की जनसंख्या के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से जो अपेक्षाएं हैं, उस दिशा में शीघ्रता से काम करने होंगे। नए मेडिकल महाविद्यालयों

की स्थापना, स्नातक व स्नातकोत्तर दोनों स्तर की मेडिकल शिक्षा में सीटों की बढ़ोतरी आदि से देश की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन होने चाहिए।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा है कि देश में मेडिकल शिक्षा क्षेत्र का वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक विस्तार होना चाहिए। नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना, नए नर्सिंग महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा, देश में नए मेडिकल महाविद्यालयों की स्थापना आदि से चिकित्सा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने की दिशा खुली है। यह बदलाव स्वागत योग्य है। अभाविप मांग करती है कि मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना आम भारतीय के लिए आर्थिक पक्ष से आसान हो सके, इसलिए प्रयास किए जाएं।

अभाविप के मेडि विजन आयाम के राष्ट्रीय संयोजक अभिनंदन बोकरिया ने कहा कि विदेश जाकर मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रों की एक बड़ी संख्या है। वर्तमान में देश में एमबीबीएस सीटें 1,01,043 हो गई हैं तथा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ी है, यह अभिनंदनीय है। अभाविप मांग करती है कि देश में जिला स्तर पर एक मेडिकल महाविद्यालय हो तथा देश की आवश्यकता अनुरूप मेडिकल शिक्षा का विस्तार हो। ■

यूपीपीएससी में छात्राओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व गौरवान्वित करने वाला क्षण : अभाविप

3

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 चयनित सभी अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने शुभकामनाएं दी हैं। अभाविप की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में छात्राओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व गौरवान्वित करने वाला क्षण है। यूपीपीएससी-2022 परीक्षा में सर्वाधिक नारी शक्ति की सफलता ने समाज को एक नयी दिशा प्रदान की है। अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि उत्तर

प्रदेश लोक सेवा आयोग में नारी शक्ति की सफलता ने समाज को एक नया प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। यूपी सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभ्युदय योजना से काफी संख्या में विद्यार्थी लाभांशित होकर चयनित हो रहे हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य हेतु मंगलकामनायें व कामना करते हैं कि आप सभी के योगदान से उत्तर प्रदेश स्वर्णिम कीर्तिमान रचेगा। यूपीपीएससी-2022 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है जो प्रशंसनीय है, परीक्षा में चयनित शीर्ष-10 अभ्यर्थियों में 8 छात्राओं का चयन नारी शक्ति को एक बेहतर दिशा दिखाई है। ■

देश में पेपर लीक की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक, रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं : अभाविप

दे

श में बढ़ती पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों को चिंता में डाल दिया है। आए दिन विभिन्न राज्यों से अलग-अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही है।

महज दो साल के भीतर अलग-अलग राज्यों में दर्जन से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। देशभर में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चिंता व्यक्त की है और इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की मांग की है। अभाविप ने 16 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पिछले दिनों अलग-अलग राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं व बोर्ड परीक्षाओं आदि के आयोजन के दौरान जिस तरह लगातार प्रश्नपत्र लीक होने व अन्य अनियमितताएं सामने आई हैं, वह बेहद चिंताजनक है।

अभाविप की विभिन्न राज्य इकाइयों द्वारा उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पेपरलीक की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अभाविप का मानना है कि पेपरलीक की घटनाओं से देश के युवाओं में असंतोष तथा चिंताएं बढ़ रही हैं, सरकार को इस समस्या का जड़ उन्मूलन करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने होंगे।

देश में पारदर्शी तथा व्यवस्थित ढंग से परीक्षाओं के आयोजन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को शीघ्र प्रयास करने चाहिए। बीते महीनों में जिस प्रकार से कई राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक तथा

पेपर लीक पर रोक की मांग को लेकर अभाविप ने किया तेलंगाणा राज्य लोक सेवा आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन

तेलंगाणा में आयोजित परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं में संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तेलंगाणा राज्य लोक सेवा आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन किया। अभाविप ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने एवं दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया और उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की। विश्वविद्यालय परिसर में टेंट लगाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर अभाविप कार्यकर्ता खुले में धरने पर बैठ गए। अभाविप ने टीएसपीएससी के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके अलावा अभाविप ने हैदराबाद के बाहरी इलाके कुथबुल्लापुर में आईडीपीएल में भी विरोध प्रदर्शन किया। वारंगल में छात्र समूहों द्वारा विरोध-प्रदर्शन जारी रहा। परिषद ने नेतृत्व में छात्रों ने हनमकोंडा में भी धरना दिया।

अभाविप ने कहा कि पेपर लीक होने के बाद कई दिन बीत गए हैं, लेकिन सभी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस तरह की घटनाएं छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात है। पेपर लीक की घटनाओं में बढ़ोत्तरी एवं उस पर कठोर कदम नहीं उठाया जाना चिंतनीय है। अभाविप ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण को निष्पक्ष तरीके जांच करवाएं एवं पेपर लीक घटना में संलिप्त सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजें एवं उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाएं। बार-बार पेपर लीक की घटना होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।





भ्रष्टाचार आदि घटनाएं हुईं, वह बेहद निंदनीय हैं। अभावविप मांग करती है पेपरलीक की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं।

पिछले दो सालों में राजस्थान से लेकर तेलंगाना, बिहार तक दर्जन से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक

देश के कई राज्यों में परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक की घटनाएं खबरें आती रहती हैं। राजस्थान में होने वाले कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से लेकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, रीट, पटवारी तक की परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। छात्र राज्य सरकार की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना में दसवीं परीक्षा शुरू होने के कुछ समय पहले ही तेलगु भाषा का पेपर लीक हो गया। इसी प्रकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने नकल के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात की।

गुजरात में कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए। बता दें कि गुजरात पंचायत लोक सेवा आयोग ने 29 जनवरी को परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दी थी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में जेओए आइटी पेपर लीक की घटना सामने आया। मध्यप्रदेश में एनएचएम पेपर लीक की घटना हुई जिसका पर्दाफाश पांच अप्रैल को मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने की। पिछले साल बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का पेपर लीक हो गया था जिस कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। इसके अलावा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधीनस्थ होने वाले स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। वहीं उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का पेपर भी लीक हो चुका है। इसके अलावा यूपी टेट परीक्षा के पेपर परीक्षा के पहले वायरल हो गया था, जिस कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा। वर्ष 2022 में महाराष्ट्र बोर्ड के 12 वीं कक्षा के रसायन विज्ञान का पर्चा लीक हो गया था। हरियाणा में भी 2022 में 12 कक्षा के हिन्दी विषय का पेपर लीक हो गया था, यह परीक्षा शुरू होने से महज 15 मिनट पहले ही लीक हुआ था। ■

भारतीय भाषाओं में फार्मैसी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और आर्किटेक्चर की पुस्तकें तैयार करने की पहल स्वागतयोग्य : अभावविप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के अध्यक्ष टी.जी. सीताराम ने 30 मार्च 2023 को कहा कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मैसी और आर्किटेक्चर की पुस्तकें हिंदी के अलावा 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराए जाएंगे। एआईसीटीई अध्यक्ष के इस घोषणा का अभावविप ने स्वागत किया है और कहा है कि भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं, संस्कृति एवं संस्कार की वाहक भी हैं। भारतीय भाषाओं में नवीन विषयों से संबंधित ज्ञान के अवसर उपलब्ध होने तथा भाषाई बाधा दूर होने से विशेषतया देश के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की इन विषयों में नामांकन बढ़ने की संभावनाओं का निश्चित ही विस्तार होगा। अभावविप ने कहा है कि जयपुर में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में विस्तृत चर्चा के बाद यह स्पष्ट मत दिया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों की पुस्तकें भारतीय

भाषाओं में आनी चाहिए, जिससे भाषाई बाधा के कारण छात्रों के ज्ञानार्जन की समस्याएं दूर हो सकें। 'स्वभाषा में सम्पूर्ण ज्ञान' के भाव को इस तरह के कदम से प्रोत्साहन मिलेगा और देश की युवा पीढ़ी अपनी भारतीय परंपराओं में निहित ज्ञान के साथ नवीन विषयों को सहजता के साथ अपनी स्वभाषा में आत्मसात कर सकेगी।

विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय भाषाओं में हमारी ज्ञान परंपरा संरक्षित है। हमारी शिक्षा व्यवस्था के आधुनिक मूल्यों को भारतीय परंपरा में निहित मूल्यों के साथ जोड़ा जाना अत्यावश्यक है। भारतीय भाषाओं में आधुनिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करना स्वागतयोग्य कदम है। अभावविप इस संबंध में स्पष्ट मत रखती है कि इन पुस्तकों का अनुवाद पठनीय तथा सरल होना चाहिए जिससे ज्ञान प्राप्ति में भाषाई जटिलताएं बाधा न बने। ■



उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित वर्गों के छात्रों की ड्रॉप-आउट संबंधी समस्या की हो पारदर्शी जांच: अभाविप

शि

क्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018 से 2023 के बीच आरक्षित वर्ग के 19 हजार से अधिक छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान लिखित प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े साझा किए। उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) एवं भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2018 से 2023 तक ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या 19, 256 है।

आरक्षित वर्गों के छात्रों द्वारा पढ़ाई को बीच में छोड़ने के संबंध में राज्यसभा में केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 30 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस विषय को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर छात्रों के ड्रॉप-आउट के पीछे विभिन्न संभावित कारणों जैसे- रोजगार मिलने, दूसरे पाठ्यक्रम या अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने के कारण अपने पूर्व संस्थान छोड़ने या कथित भेदभाव आदि कारणों की जांच करने की मांग की है, जिससे इस मामले में उचित कदम उठाए जा सकें।

अभाविप का कहना है कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, शैक्षणिक संस्थानों में देश का भविष्य आकार लेता है। शैक्षणिक संस्थानों का वातावरण रचनात्मक तथा छात्रों के

सरकार ने कहा ड्रॉप आउट के पीछे कई कारण

ड्रॉप आउट की समस्या पर सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षा में छात्रों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे वह एक से दूसरे संस्थानों में जा सकते हैं या किसी एक पाठ्यक्रम से दूसरे में उसी या अन्य संस्थानों में जा सकते हैं। संस्थान बदलने या बीच में पढ़ाई छोड़ने की मुख्य कारण अन्य पाठ्यक्रम या संस्थान में प्रवेश लेने का निजी कारण होते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार का कहना है कि आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ शैक्षिक संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं होते।

अनुकूल होना चाहिए, हमारे परिसरों में समानता तथा समता शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सभी हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की गति बढ़ानी होगी।

पिछले कई वर्षों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम आदि के कुछ छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ने के संभावित कारणों की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन दर बढ़ाने के लिए तेजी से प्रयास आवश्यक हैं। देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए समान अवसर होने चाहिए तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ■

शासन के कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं : अभाविप

छ

तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा जगदलपुर में आयोजित मशाल यात्रा में 31 मार्च 2023 को मशाल की आग से नेहरू छात्रावास जगदलपुर के नवमी कक्षा के नाबालिग दो छात्र बुरी तरह से झुलस गए थे, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल छात्रों के परिवारजनों द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रों को कांग्रेस के प्रत्येक कार्यक्रम में ले जाने की बात स्वीकार की गई है किंतु प्रशासन उदासीन रवैया दिखाते हुए वर्तमान समय तक इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने

पर अभाविप ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। अभाविप ने कहा है कि कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिकरण को बढ़ावा दे रही है, इससे छात्र वर्ग में भारी नाराजगी है। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन भी किया था, किंतु वर्तमान समय तक शासन के भय में आकर संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं होना प्रशासन और कांग्रेस की एकरूपता को प्रदर्शित कर रही है। वे शासन के कर्मचारी नहीं होकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ■

95 साल की एथलीट दादी ने पोलैंड में रचा इतिहास, तीन गोल्ड जीत कर बढ़ाया भारत का मान

खे

लों में भारत का मान बढ़ाने के लिए आमतौर पर देशवासियों की उम्मीदें युवा खिलाड़ियों पर टिकी रहती हैं। हमारे देश में युवा प्रतिभाएं ही नहीं, बल्कि 90 की उम्र पार चुकी महिला एथलीट भी स्वर्ण पदक जीत कर ला रही हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाली 95 वर्ष की एथलीट दादी भगवानी देवी डागर ने पोलैंड में आयोजित नौवीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट इंडोर चैंपियनशिप-2023 में तीन स्वर्ण पदक जीत कर भारत की झोली में डाले हैं। भगवानी देवी दादी ने 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले पिछले साल 2022 में उन्होंने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट इंडोर चैंपियनशिप में तीन पदक जीते थे। पूरे देश में उनकी बहुत सराहना हुई थी वो देखते ही देखते चर्चा में आ गयी थीं। लाखों करोड़ों महिलाओं के दिल में उन्होंने उम्मीद की किरण जगायी।

तीन स्वर्ण पदक जीत कर 4 अप्रैल 2023 की सुबह भारत



लौटी भगवानी देवी डागर का दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हज़ारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उत्साह और जोश से भरपूर दादी को स्वर्ण रजत या कांस्य पदक की कोई जानकारी नहीं है। बस उन्होंने अपने मन में ठाना था कि वो खेलों में पीला मेडल (स्वर्ण

पदक) लेकर आएंगीं। हवाई अड्डे पर संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं पीला मेडल जीतूंगी। मेरी जीत का राज है कि मैं देसी घी में बना खाना खाती हूँ। शाम को पार्क में घूमती हूँ। मैं देश के सभी नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि खेले कूदो, दौड़ लगाओ, दूसरे देशों में जाकर पदक जीत कर अपने देश का नाम रोशन करो। मैं आगे भी जब कहीं जाऊंगी तो हमेशा अपने देश के लिए गोल्ड ही जीत कर लाऊंगी। ■

अभाविप कार्यकर्ता पर प.बंगाल के बैरकपुर में हमला

वि

धानसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं बढ़ चुकी हैं। बताया जाता है कि बंगाल में लगातार विरोधी विचार एवं दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं उसके वृद्ध पिता (सेवानिवृत्त सैनिक) के साथ मार-पीट की गई, जिसकी सूचना अभाविप ने सात मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। अभाविप ने अपने कार्यकर्ता तथा उनके परिवारजन पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए हमले की कड़ी निन्दा की है। अभाविप का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा समर्थित हिंसा लगातार जारी है, जिसके कारण आम जनमानस का जीवन कठिन हो गया है।

परिषद का कहना है कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अभाविप की स्थानीय इकाई के सहमंत्री जगदीश महतो, उनके वृद्ध पिता तथा भाई के साथ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा की

गई हिंसा में अभाविप कार्यकर्ता तथा उनके परिवारजन को गंभीर चोटें आई हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट तथा हिंसा की शर्मनाक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

अभाविप ने आरोप लगाया है कि बंगाल, तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक हिंसा का गढ़ होता जा रहा है। लोकतांत्रिक देश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का अधिनायकवादी चरित्र, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए दिन-प्रतिदिन नई-नई समस्या पैदा कर रहा है। राज्य सरकार के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता पर लगातार हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों अभाविप के एक कार्यकर्ता को फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बैरकपुर की दूसरी घटना में अभाविप कार्यकर्ता के साथ हिंसा हुई। ये घटनाएं शर्मनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल सरकार हिंसा की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। ■



वैदिक ज्ञान परंपरा को सर्वसुलभ बनाने के लिए वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुभारंभ



भारत की महान वैदिक ज्ञान परंपरा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल बनाया गया, जिसका लोकार्पण केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। पोर्टल लोकार्पण के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार तकनीक के माध्यम से भारत के प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों के ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रख रही है। इस पोर्टल के माध्यम से युवा पीढ़ी वेदों व उपनिषदों के ज्ञान व परंपरा को आगे बढ़ा सकेगी।

वेदों को समझना हुआ आसान, सरल भाषा में तैयार किया गया है वैदिक पोर्टल

वैदिक ज्ञान परंपरा को सर्वसुलभ बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पाठक सरल भाषा में वेदों को समझ सकते हैं। इसमें 18 हजार से अधिक वैदिक मंत्रों के ऑडियो एवं विजुअल उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर वैदिक मंत्रों को सरल एवं सहज भाषा में समझाया गया है। इसके साथ ही यह शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को

समझने में सहयोग करेगा और साथ ही जनसाधारण को प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। पोर्टल को तैयार करने में वेदों को जानने वाले विद्वान, वेद शोध संस्थानों, वेदपाठी परिवारों ने सहयोग किया है। कला केंद्र ने वेदों के ज्ञान को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया है।

भारत की वैभवशाली संस्कृति को दर्शाएगा 'कला वैभव'

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 64 कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम 'कला वैभव' भारत की वास्तुकला, चित्र, नाट्य, संगीत आदि समस्त कलाओं से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा और इससे विश्व को भारत की वैभवशाली संस्कृति का समृद्ध इतिहास जानने में सुविधा होगी। गृह मंत्री ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल के साथ-साथ वर्चुअल म्यूजियम 'कला वैभव' का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी, आईजीएनसीए के अध्यक्ष राम बहादुर राय, कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ■

ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने तमिल भाषा व साहित्य पर शोध के लिए आईसीसीआर के साथ किया समझौता

31

मेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की पीठ स्थापित होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति पर शोध को बढ़ावा देना है। इस संबंध में हाल ही में अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय तथा आईसीसीआर बीच एक समझौता किया गया है। यह समझौता भारतीय अध्ययन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की कई वर्षों से जारी कोशिशों के तहत उठाया गया नया कदम है।

विश्वविद्यालय की प्रमुख रेणु खाटोर ने बताया कि हम इस सहयोग के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के आभारी हैं जो निश्चित रूप से हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। वह इस विश्वविद्यालय की अगुवाई करने वाली पहली प्रवासी भारतीय हैं और 2008 से इस

पद पर हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का विस्तार छात्रों के लिए शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाएगा और उन्हें वैश्विक मंच पर सफलता के लिए तैयार करेगा।

भारतीय अध्ययन की आईसीसीआर पीठ के पद पर भारत के विद्वान आसीन होंगे जो तमिल अध्ययन में विशेषज्ञ होंगे। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत असीम महाजन ने कहा कि पीठ का उद्देश्य तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति पर शोध करना और शिक्षा देना तथा शिक्षा साझेदारी को गहरा करना है। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और यह अमेरिका में बोली जाने वाली शीर्ष पांच भाषाओं में से एक है। अमेरिका में तकरीबन तीन लाख तमिल-अमेरिकी रहते हैं। यह एमओयू अमेरिकी शिक्षा और ज्ञान साझेदारी को और बढ़ाएगा तथा गहरा करेगा। ■

रांची : सरहुल पर्व पर अभाविप ने लगाए सेवा शिविर

स

रहुल पर्व के उपलक्ष्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा सेवा शिविर लगाया गया। अभाविप झारखंड के प्रांत संगठन मंत्री राजीव रंजन ने बताया कि सरहुल प्रकृति को समर्पित पर्व है, जिसे पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। सरहुल से ही वनवासियों का नववर्ष शुरू होता है। यह चैत्र माह में मनाया जाता है और यह झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इस हेतु सरहुल के पावन अवसर पर अभाविप द्वारा प्रांत भर में अलग-अलग स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए। रांची महानगर के द्वारा आयोजित सेवा शिविर में श्रद्धालुओं को चना, गुड और शर्बत दिया गया। इसी प्रकार दुमका में भी सेवा शिविर लगाकर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पलामु के मेदनीनगर में श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा कर स्वागत



किया गया। वहीं अन्य कई शिविर में श्रद्धालुओं को मौसमी फल इत्यादि वितरित किया गया।

क्या है सरहुल

सरहुल झारखंड का प्रमुख पर्व है, इस पर्व को जनजाति समाज बहुत उत्साह पूर्वक मनाते हैं। यह पर्व झारखंड के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों ओडिशा, प. बंगाल और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। प्रकृति को समर्पित सरहुल पर्व का आयोजन चैत्र माह में नववर्ष के स्वागत में मनाया जाता है। पतझड़ के बाद साल के पेड़ों से खिलने वाले फूलों का सरहुल में विशेष महत्व होता है।

चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू होकर चार दिनों तक यानी चैत्र पूर्णिमा तक चलता है। इसमें वनवासी समाज अपनी पारंपरिक वेश-भुषा में शोभा यात्रा भी निकालते हैं। ■



राष्ट्रीय कला मंच द्वारा आयोजित दो दिवसीय 'राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव' मुंबई में संपन्न

31

खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आयाम राष्ट्रीय कला मंच द्वारा मुंबई में दो दिवसीय 'राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव' का आयोजन किया गया था। महोत्सव में 16 राज्यों के 12 भाषाओं में 29 लघु फिल्में दिखाई गईं, जिसमें शुभम शर्मा की अलार्म घड़ी को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के रूप में चुना गया। दो दिवसीय फिल्म महोत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा, फिल्म निर्माता, निदेशक और पटकथा लेखकों व विशेषज्ञों द्वारा मास्टरक्लास का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री, पटकथा लेखक नीरज पाठक, अभिनेता योगेश सोमन, छायाकार असीम बजाज, फिल्म निर्माता गोपाल मल्होत्रा, प्राध्यापक सत्यजीत मांडले आदि ने प्रतिभागियों को फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन, छायांकन कास्टिंग इत्यादि के गुर सिखाए।

राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव के उदघाटन समारोह में प्रसिद्ध मराठी फिल्म निदेशक राजदत्त, फिल्म निर्माता तरूण राठी, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रा. मिलिंद मराठे आदि उपस्थित थे। उदघाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि भारतीय फिल्म एवं कला ने वैश्विक मंच पर अपना लोहा मनवाया है। हाल ही में भारत की फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपने पैशन के प्रति डेडिकेशन का होना बेहद जरूरी है।

मास्टर क्लास सत्र के दौरान प्राध्यापक सत्यजीत मांडले ने फिल्मों में कथा के महत्व और कहानी कहने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कथाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद हैं और हमारे आस-पास की हर चीज की अलग कहानी है। वहीं असीम बजाज ने छात्रों को सिनेमा के छायांकन से जुड़े तकनीकी पक्षों से परिचित करवाया। इस दौरान उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया। मुश्ताक

नाडियावाला ने फिल्म निर्माण में कहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एक कंपनी के विज्ञापन का उदाहरण देते हुए कहा कि दर्शक कहानी के भावों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने किसी तकनीकी पक्ष की गड़बड़ियों पर ध्यान नहीं दिया। श्री नाडियावाला ने कहा कि फिल्मों में तकनीकी पक्ष महत्वपूर्ण है परंतु कहानी और किरदार अगर जानदार हो तो तकनीकी खामियों की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव के प्रयास की सराहना की और कहा कि दूसरों को प्रभावित करना छोड़कर खुद को अभिव्यक्त करना शुरू करो। उन्होंने आने वाले फिल्म निर्माताओं को विभिन्न विचारों, कहानियों और पात्रों के साथ साहस दिखाने का आह्वान किया। इस दौरान श्री अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' की रिलीज के दौरान के संघर्षों को साझा किया। साथ ही ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने के पीछे के भाव को उजागर किया।

'अलार्म घड़ी' को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार

राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव के अंतिम दिन विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें लघु फिल्म श्रेणी में अलार्म घड़ी को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुभम शर्मा की फिल्म अलार्म घड़ी उत्तराखंड के छात्र की कहानी है, जिसमें अलार्म घड़ी की उपयोगिता एवं समय की महत्ता को दर्शाती है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के प्रमाण पत्र के साथ-साथ एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी दी गई। वहीं सर्वश्रेष्ठ संगीत 'लवबड्स' के लिए सागर मशालकर, श्रेष्ठ एडिटिंग 'विधि आटा' के लिए सुर्या तेजा को, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म 'कैनवास' के लिए संजय चंद्रशेखर को, सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी 'अलार्म घड़ी' एवं 'न्यू ईयर' के लिए शुभम शर्मा को, सर्वश्रेष्ठ पटकथा (स्क्रिप्ट) 'ए फ्लाइट ऑफ लॉस्ट ड्रीमी बर्ड' के लिए रमेश किशन को एवं नितिन कलाने को 'सुकल्या एंड पथावनी' हेतु सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। ■

भारतीय छात्र को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रताड़ित करने तथा भेदभाव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण: अभाविप

लं

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले एक भारतीय छात्र करण कटारिया पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं भारतीय होने के कारण प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। हरियाणा के रहने वाले छात्र करण कटारिया ने आरोप लगाया है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका विरोध उसने विरोध किया। डेमोक्रेसी कमेटी में अपील की लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वे लंदन स्कूल ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स छात्र संघ चुनाव भी लड़ रहे थे, लेकिन उपरोक्त कारणों से दो अप्रैल 2023 उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी गई।

भारतीय छात्र के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार की घटना पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि करण कटारिया के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेदभाव, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार तथा भारतीय पहचान के कारण प्रताड़ित किए जाने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के छात्र-छात्राओं के सबसे प्रमुख तथा विशाल छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवाओं के साथ सम्मानपूर्ण, गरिमामय, लोकतांत्रिक तथा मानवीय मूल्यों के अनुरूप व्यवहार किए जाने की पक्षधर है। अभाविप ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न छात्र संघ चुनाव जीते हैं, अभाविप शैक्षणिक परिसरों में लोकतांत्रिक मूल्यों तथा विविधता के सम्मान की पक्षधर है।

भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विविधतापूर्ण समाज तथा संस्कृति को सभी क्षेत्रों में समान अवसर तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर समूचे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभाविप का स्पष्ट मत है कि छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण हितधारक मानते हुए उनके मतों को गंभीरता से लेकर उचित समावेशन होना चाहिए। किसी भी



शैक्षणिक संस्थान में विविधता व सभी मतों को सम्मान तथा लोकतांत्रिक व मानवीय सरोकारों के अनुरूप गतिविधियां संचालित होनी चाहिए।

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भारतीय छात्र के साथ उनकी राष्ट्रीयता तथा वैचारिकी के लिए दुर्भावनापूर्ण व्यवहार तथा प्रताड़ित किया जाना निंदनीय है। शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राओं का स्थान महत्वपूर्ण हितधारक का है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे शैक्षणिक संस्थान को किसी भी छात्र के साथ उसकी वैचारिकी, पसंद-नापसंद या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए तथा परिसर में लोकतांत्रिक मूल्यों व विविधता के सम्मान के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहिए। भारतीय छात्र समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप अभाविप, वैश्वक छात्र समुदाय से करण कटारिया के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार किए जाने के पक्ष में खड़े होने का आह्वान करती है। ■



उड़ीसा में वनवासी विद्यार्थियों के लिए अभाविप ने आयोजित किया एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम

31

खिल भारतीयविद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा जनजातीय छात्रों के करियर को दिशा देने एवं उनके व्यक्तित्व विकास के लिए एक्सपोजर विजिट नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उड़ीसा प्रांत में गत 17-19 मार्च को हुआ। कार्यक्रम में वनवासी बाहुल्य आठ जिले के 46 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं अभाविप के पूर्व अखिल भारतीय जनजातीय कार्य प्रमुख पी. सूर्यनारायण सूरी, रिजर्व बैंक भुवनेश्वर शाखा के प्रबंधक प्रह्लाद प्रधान, अभाविप के जनजातीय कार्य सह प्रमुख प्रमोद राउत उपस्थित थे।

एक्सपोजर विजिट में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पी. सूर्यनारायण सूरी ने कहा कि जंगल में टाइगर और ट्राइबल को किसी से डर नहीं लगता। वनवासी समाज किसी से नहीं डरता है। वनवासी समाज ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। देश की रक्षा के लिए इस समाज ने अंग्रेज और मुगलों को उचित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समर्थ और स्वावलंबी बन कर अपने देश को आगे लेकर जाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बैंक मैनेजर, जर्नालिस्ट, वकील, किसान, प्राध्यापक इत्यादि बनना पड़ेगा। वहीं रिजर्व बैंक के शाखा प्रबंधक प्रह्लाद प्रधान ने प्रतिनिधियों को नवोन्मेषी विचार के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

अभाविप के अखिल भारतीय जनजातीय कार्य सह प्रमुख प्रमोद राउत के अनुसार कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यार्थियों को करियर के साथ-साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को आगे ले जाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का उद्देश्य सुदूर क्षेत्र में रहने वाले वनवासी छात्रों के व्यक्तित्व को निखारना एवं उनकी प्रतिभा को उचित

मंच दिलाना है। उन्होंने कहा कि एक्सपोजर विजिट के तहत छात्रों को आईआईटी, एनआईटी जैसे शैक्षिक संस्थान का भ्रमण कराना, वहां के प्राध्यापकों एवं अध्येताओं से संवाद स्थापित कर उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसी प्रकार खेल में रुचि रखने वाले छात्रों को खेल क्षेत्र के महारथियों से मिलाना, संवाद स्थापित करना, उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं से परिचित करवाना, विभिन्न स्पोर्ट्स कंप्लेक्स, इंडोर-आउटडोर के स्टेडियम का भ्रमण कराना है ताकि वे इस दिशा में प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने बताया कि एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत छात्रों ने आईटीआईटी (भुवनेश्वर), एसडीआई (भुवनेश्वर), परिसर पुस्तकालय, विभाग इत्यादि जगहों का भ्रमण करने के साथ ही संस्थान के प्राध्यापक एवं छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान वनवासी समाज के विद्यार्थियों के साथ प्रतिभावान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बैंक मैनेजर आदि ने संवाद किया और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया, ताकि विद्यार्थी इनसे प्रेरणा लेकर अपने करियर को नई दिशा दे सकें। समारोह में मुख्य अतिथि सोमनाथ हांसदा (मुख्य सर्तकता अधिकारी, नाल्को), प्रो. आशुतोष मंडावी (प्राध्यापक, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर) मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथि द्वय ने प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने जगन्नाथ पुरी गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य से भेंट की एवं उनसे आशीर्वाद लिए। इस दौरान प्रतिनिधियों ने जगन्नाथ मंदिर एवं लिंगराज मंदिर में दर्शन किए। श्री रावत ने बताया कि एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का प्रारम्भ उड़ीसा के वनवासी छात्रावासों से हुआ है, जिसे देश भर के सभी राज्यों के छात्रावासों में रहने वाले वनवासी छात्रों के बीच ले जाना है। मई के दूसरे सप्ताह में झारखंड में भी इसी प्रकार के एक्सपोजर विजिट के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ■

परिषद् गतिविधियां



विकासार्थ विद्यार्थी द्वारा लखनऊ में आयोजित 'सृष्टि मंथन' कार्यशाला को संबोधित करते अभाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत



अभाविप ओड़िशा द्वारा आयोजित एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के तहत जनजातीय छात्रों का कौशल विकास संस्थान, भुवनेश्वर का भ्रमण

राष्ट्रीय विद्यार्थी फिल्म महोत्सव की झलकियां

